Registration No. RAJBIL /2016 / 69093
OFFICIAL PUBLICATION OF LAGHU UDYOG BHARATI

लघु उद्योग भारती

UDYOG TIMES

Volume - 09 Issue - 08 June - 2026
Total Pages - 44 Price - Rs. 100

उद्यमिता विशेषांक

उत्तर भारत के प्रेरक लघु उद्यमी

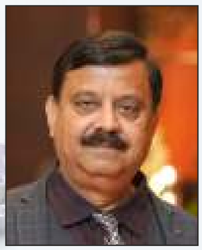
परवीन परगाल गुप्ता
जम्मू एंड कश्मीर

देविंदर कौशल
पंजाब

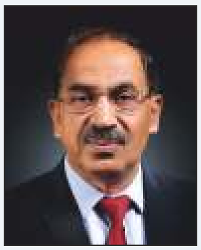
भूपिंदर कुमार
पंजाब

राकेश आर. अग्रवाल
चंडीगढ़

दीपक गोयल
उत्तराखंड

गौतम चौधरी
हरियाणा

रीता मित्तल
उत्तर प्रदेश

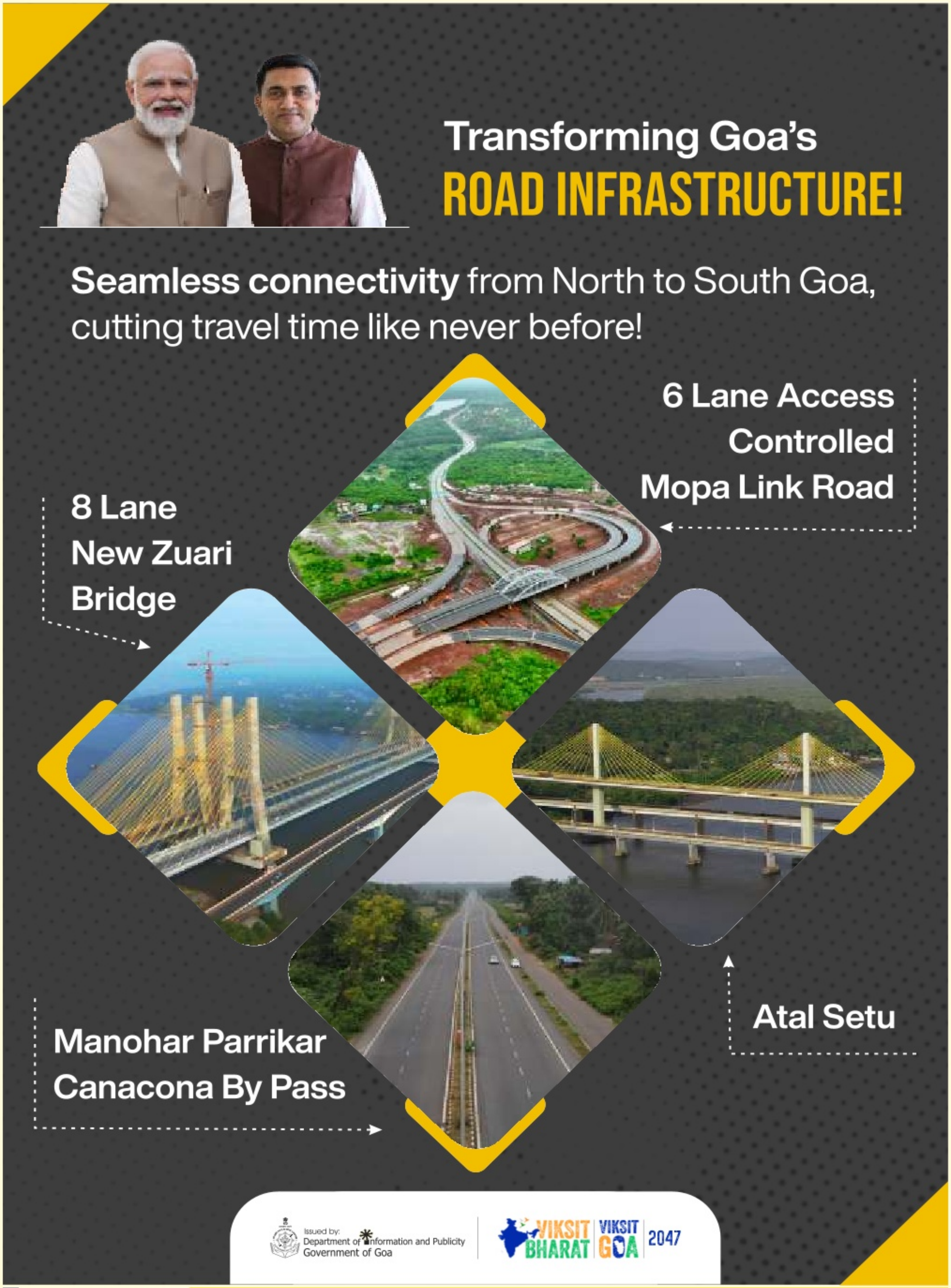

Transforming Goa's
ROAD INFRASTRUCTURE!
Seamless connectivity from North to South Goa, cutting travel time like never before!
6 Lane Access Controlled Mopa Link Road
8 Lane New Zuari Bridge
Atal Setu
Manohar Parrikar Canacona By Pass
Issued by: Department of Information and Publicity Government of Goa
VIKSIT BHARAT
VIKSIT GOA
2047

UDYOG TIMES

OFFICIAL PUBLICATION OF LAGHU UDYOG BHARATI

Volume -9 Issue - 8 June 2026

Editorial Board

■ ***Patron***

Shri Madhusudan Dadu, National President	098102-56494
Shri Prakash Chandra ji, National Org. Secretary	099299-93660
Shri Om Prakash Gupta, National Gen. Secretary	095602-55055

■ ***Editor***

Dr. Kirti Kumar Jain	094141-90383

■ ***Co-Editor***

Dr. Sanjay Mishra	098295-58069

विवरणिका

Editorial	03
Vibrant Gujarat Regional Conference	04
वैश्विक परिदृश्य में कच्चे तेल की	05
MSMEs & ESG Reporting	07
How TAMIL NADU can Achieve One Trillion	09
उद्यम यात्रा – परवीन परगल, जम्मू कश्मीर	13
LUB Gujarat 101 Women Entrepreneurs	16
उद्यम यात्रा – देविंदर कौशल–भूपेंद्र कुमार, पंजाब	17
उद्यम यात्रा – राकेश आर. अग्रवाल, चंडीगढ़	21
उद्यम यात्रा – दीपक गोयल, उत्तराखंड	23
उद्यम यात्रा – गौतम चौधरी, हरियाणा	25
उद्यम यात्रा – रीता मित्तल, उत्तर प्रदेश	29
Rajasthan Govt. MSME Day	32
LUB's News in Brief	35

Important Notice : As per Board Resolution passed in the meeting of Board of Directors of Laghu Udyog Bharati held on 24.04.2026 at Jaipur, Shri Madhu Sudan Dadu, All India President of Laghu Udyog Bharati has been appointed as publisher of Udyog Time, a bilingual National Monthly Magazine with immediate effect.

Annual Membership: Rs. 1200 Including Postage

Corporate & Head Office :
Shri Vishwakarma Bhawan 48, Deen Dayal Upadhyay Marg, Rouse Avenue, New Delhi-110002
Website : www.lubindia.com
Email : headoffice@lubindia.com
Ph.: 011-23238582
Registered Office :
Plot No. 184, Shivaji Nagar, Nagpur-440011
Ph.: 0712-2533552

India's Trade reached to 5.4 pc to touch $1.84 Trillion in Q4 of FY 2025-26

Editorial

Dr. Kirti Kumar Jain

kkjain383@gmail.com

India's total merchandise and services trade expanded by 5.4 per cent year-on-year during January-March in the financial year 2025-26 to reach $1.84 trillion, reflecting a stable performance despite the uncertainties in global markets, according to NITI Ayog.

India's trade performance in Q4 FY'2025-26 underscored the continued resilience of the external sector, supported by robust growth in services trade. While merchandise exports moderated and imports increased, the composition of trade remained broadly stable.

Services trade remained a key source of strength, with exports growing by 9. Per cent, outpacing import growth and sustaining a strong services surplus. India retained its position as the world's eighth-largest services exporter in 2025, with services exports recording a CAGR of 10.3 per cent during 2015-2025, significantly above the global average.

The analysis highlights that India's export strength remains concentrated in formulations, particularly retail medicaments and generic drugs, where it has established a strong presence across global markets.

Overall, India's total trade reached $1.84 trillion during FY2025-26, with exports growing by 4.2 per cent and imports by 6.5 per cent, highlighting the continued dynamism of India's engagement with the global economy.

□□□

Vibrant Gujarat Regional Conference & Exhibition-2026
‘Regional Aspirations, Global Ambitions’

The Vibrant Gujarat Regional Conference (VGRC) for the Central Gujarat region was recently held in Vadodara from June 29 to July 3 at GSFC University. The summit brought together policymakers, global diplomats, and industry leaders to boost local investments and showcase the region's manufacturing prowess.

In the inaugural function; **Chief Minister Shri Bhupendra Patel** urged the regional industries to become partners in Viksit Bharat journey as India needs to transform its regional strengths into national capabilities, local innovations into global compe-titiveness & industrial growth into strategic strength. He said that Gujarat can play a pivotal role in achieving the goal of self-reliance as the state possesses a robust industrial base, a skilled workforce, and an entrepreneurial spirit.

He said that from advanced manufacturing to cutting-edge research, Gujarat has the potential to become a major hub for defence production and technology.

The conference placed a major emphasis on Central Gujarat's 10 districts, which account for roughly 28% of the state's total manufacturing output.

LUB’s Gujarat delegation led by State President Shri Ishwar Bhai Patel with Karnawati Sambhag General Secretary Shri Ashokbhai Patel greets the Chief Minister Shri Bhupendra Bhai Patel in the Inaugural Ceremony of Vibrant Gujarat Regional Conference at Vadodara on 29th June, 2026.

Key highlights and takeaways from the event included:

- **Focused Sectors:** Deliberations and seminars heavily focused on future-ready industries including semiconductors, electronics (ESDM), biotechnology, green hydrogen, aerospace and defence, and pharmaceuticals.
- **Exhibitions and Meetings:** The event featured over 30 strategic seminars, more than 151 expert speakers, and extensive B2B and B2G meetings to promote MSMEs, startups, and vendor development.
- **Global Participation:** Delegates and international partnerships from partner countries like Japan, Singapore, the UAE, Ukraine, and Rwanda took part in the summit.
- **Tourism and Heritage:** Alongside industry, the conference highlighted the region's tourism potential, heavily promoting local heritage sites and eco-tourism corridors, including the Statue of Unity and the Champaner-Pavagadh Archaeological Park. Special sections dedicated to the culture and arts of regional tribal communities.
- **MSME Pavilion**: Showcased industrial engineering, tech solutions, and local manufacturing capabilities.
- **Crafts Village & Swadeshi Haat**: Promoted traditional handicrafts and local artisans.

On this occasion, Union Minister of Petroleum and Natural Gas Shri Hardeep Singh Puri, Union Minister of Jal Shakti Shri CR Patil and many other dignitaries were present. ❑ ❑ ❑

वैश्विक परिदृश्य में कच्चे तेल की गिरती कीमतों का गणित

(अमेरिकी-ईरान तनाव में तेल-गैस की बाधित आपूर्ति ने उद्योगों के समक्ष ऊर्जा संकट पैदा किया)

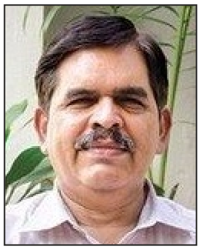

सामयिक

डॉ. अश्वनी महाजन

जाने-माने आर्थिक विश्लेषक

राष्ट्रीय सह-संयोजक, स्वदेशी जागरण मंच

पूर्व प्रोफ़ेसर, दिल्ली विश्वविद्यालय

ashwanimahajan@rediffmail.com

अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते और होर्मुज जलडमरूमध्य (स्ट्रेट ऑफ़ हॉर्मुज़) के खुलने के बाद, कच्चे तेल की कीमतें अचानक गिरकर लगभग 70 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल हो गई हैं, जिसे कोई बड़ी हैरानी की बात नहीं माना जा रहा है। अब सवाल यह है कि अगर दोबारा युद्ध नहीं छिड़ता है, तो तेल की संतुलन कीमत क्या होगी।

हाल के भू-राजनीतिक तनावों के दौरान, ऐसी व्यापक अटकलें थीं कि कच्चे तेल की कीमतें 150 डॉलर प्रति बैरल या उससे भी ज़्यादा हो सकती हैं, जिससे दुनिया भर में महंगाई बढ़ सकती है। असल में हालात इन अटकलों के आस-पास भी नहीं पहुँचे; और युद्ध के सबसे तनावपूर्ण दौर में भी, कच्चे तेल की कीमतें 95 डॉलर से 120 डॉलर प्रति बैरल के बीच रहीं और औसतन 100 डॉलर प्रति बैरल के आसपास बनी रहीं। असल में, जिन लोगों ने 150 डॉलर प्रति बैरल या उससे ज़्यादा कीमत का अनुमान लगाया था, वे तेल बाज़ार की मांग और आपूर्ति के आपसी तालमेल को नहीं समझ पाए। हमें यह समझने की ज़रूरत है कि बाज़ार में किसी भी चीज़ की कीमत मांग और आपूर्ति की ताकतों से तय होती है, और तेल भी इस नियम से अलग नहीं है।

पिछले तीन-चार महीनों में दुनिया ने महसूस किया है कि तेल बाज़ार में बड़े बदलाव हो रहे हैं। इसने पुरानी धारणाओं को गलत साबित कर दिया है कि मांग 'स्थिर' होती है और आपूर्ति कुछ बड़े आपूर्तिकर्ता देशों के नियंत्रण में होती है, चाहे वे कार्टेल (समूह) के तौर पर काम करें या स्वतंत्र रूप से। आज, तेल की कीमतें मांग और आपूर्ति की स्वतंत्र ताकतों से प्रभावित हो रही हैं और 'मांग में कमी' और 'आपूर्ति में रुकावट' जैसी स्थितियों का सामना कर रही हैं।

अब कीमत बेलोचदार नहीं रही तेल की माँग पहले, तेल की मांग पर कीमत का ज़्यादा असर नहीं पड़ता था (यानी यह कीमत बेलोचदार थी)। इसलिए, कच्चे तेल की ज़्यादा कीमतों का भारत जैसे देशों पर भारी बोझ पड़ता था, जो विदेशी आपूर्ति पर बहुत ज़्यादा निर्भर थे- तेल के लिए 88 प्रतिशत और गैस के लिए लगभग 50 प्रतिशत तक। लेकिन हाल ही में 'मांग में कमी' की एक नई स्थिति उभरने लगी है, जिससे मांग कम हो रही है, खासकर तब जब कच्चे तेल की कीमतें ज़्यादा होती हैं।

मांग की ताकतों का बारीकी से विश्लेषण करने पर पता चलता है कि लगभग 100 डॉलर प्रति बैरल की कीमत पर मांग में कमी साफ दिखती है। मुख्य रूप से ऐसा लोगों की वास्तविक क्रय शक्ति पर पड़ने वाले असर के कारण होता है, जिसे हम 'वास्तविक आय प्रभाव' कहते हैं। माँग में यह कमी 'प्रतिस्थापन प्रभाव' से होती है, क्योंकि तेल की ज़्यादा कीमत के कारण लोग इसके विकल्पों का इस्तेमाल करने लगते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे-जैसे कच्चे तेल और पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं, लोग विकल्प अपनाना शुरू कर सकते हैं; जैसे पेट्रोल और डीज़ल गाड़ियों की जगह इलेक्ट्रिक गाड़ियां, गैस स्टोव की जगह इलेक्ट्रिक इंडक्शन प्लेट वगैरह। अगर गैस और तेल की सप्लाई में कोई रुकावट

आती है, तो गैस और तेल आधारित औद्योगिक इकाइयां या तो बंद हो सकती हैं या दूसरे विकल्पों पर जा सकती हैं।

बिजली बनाने के लिए भी, भारत समेत कई देश पहले से ही सोलर, विंड और न्यूक्लियर पावर की ओर बढ़ रहे हैं। हमें यह भी समझना होगा कि जब कच्चे तेल की ऊंची कीमतों की वजह से तेल की माँग कम हो जाती है, लेकिन एक बार जब माँग कम हो जाती है, तो वह 'हमेशा के लिए' कम हो जाती है; और ऐसे में यदि कच्चे तेल की कीमतें कम भी हो जाएं, तो भी माँग कभी अपने पुराने स्तर पर वापस नहीं आएगी।

सप्लाई में रुकावट का असर

हमने पहले देखा है कि कोविड–19 के शुरुआती दिनों में जब मांग बहुत कम हो गई थी, तो कच्चे तेल की कीमत नेगेटिव हो गई थी, क्योंकि मांग न होने पर भी तेल निकालना बंद करना मुमकिन नहीं होता। ईरान के साथ भी ऐसा ही हुआ था; तेल न बिक पाने के कारण उनके पास तेल को समुद्र में बहाने के अलावा कोई चारा नहीं था। इसलिए, जो तेल उत्पादक और सप्लायर कीमतें बढ़ाने के लिए अपनी मोनोपॉली (एकाधिकार) का इस्तेमाल करते थे, वे अब मांग में भारी कमी के कारण वही रणनीति नहीं अपना पाएंगे। भविष्य में यह स्थिति और तेज़ी से बढ़ सकती है क्योंकि अब तेल के कई विकल्प सामने आ रहे हैं।

इसके अलावा, हम समझते हैं कि कई अर्थव्यवस्थाओं में तेल से होने वाली कमाई ही राजस्व का मुख्य स्रोत होती है, इसलिए उन्हें कीमतें गिरने पर भी तेल एक्सपोर्ट करना पड़ता है, कभी–कभी तो निकालने की लागत से भी कम कीमत पर।

1970 के दशक से दुनिया ने तेल उत्पादकों और एक्सपोर्टर्स का चालाक कार्टेल (समूह) देखा है, जब उन्होंने 'ऑयल प्रोड्यूसिंग एंड एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़' (ओपेक) बनाया था। लेकिन अब कुछ अहम देश OPEC से बाहर निकल चुके हैं और वे तेल की सप्लाई कम करने के ओपेक के फैसलों से बंधे नहीं रहना चाहते। पिछले 10 सालों में, जिन सदस्य देशों ने ओपेक छोड़ा है या जिन्हें सस्पेंड किया गया है, उनमें कतर, संयुक्त अरब अमीरात (यूएई), इंडोनेशिया, अंगोला और इक्वाडोर शामिल हैं। अभी ओपेक में सिर्फ़ 11 सदस्य देश बचे हैं, और जो देश बाहर निकल चुके हैं, वे ज़ाहिर है कि ओपेक के प्रोडक्शन से जुड़े आदेशों को नहीं मानते।

इसके अलावा, अमेरिका और यूरोपीय देशों ने रूस और वेनेजुएला जैसे बड़े तेल उत्पादक देशों से तेल खरीदने पर रोक लगा दी थी। अब अमेरिका खुद वेनेजुएला की तेल सप्लाई को कंट्रोल कर रहा है, जबकि रूस पर अमेरिकी प्रतिबंध जारी हैं। पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों से किसी तरह बचने के लिए, रूस भारत और चीन जैसे मित्र देशों को लगभग 40 प्रतिशत सस्ती कीमत पर तेल बेच रहा है। वहीं, वेनेजुएला, जो सबसे बुरे आर्थिक संकट का सामना कर रहा था, उसे भी अमेरिका के कब्ज़े में आने से पहले कम कीमत पर तेल बेचने के लिए मजबूर होना पड़ा था।

ओपेक की कम होती मोनोपॉली पावर, कुछ देशों द्वारा मार्केट प्राइस से कम कीमत पर तेल बेचना और कुछ अन्य तेल एक्सपोर्ट करने वाले देशों पर कमाई का दबाव – इन सबके मिले–जुले असर से कच्चे तेल की सप्लाई बढ़ जाती है। इसके अलावा, कच्चे तेल की ऊंची अंतरराष्ट्रीय कीमतों ने अमेरिका, वेनेजुएला, रूस, कनाडा और कुछ अन्य देशों से तेल की सप्लाई को भी बढ़ावा दिया है। कुल मिलाकर, कीमतों की वजह से सप्लाई में होने वाली बढ़ोतरी आसानी से 8 से 9 मिलियन बैरल प्रति दिन तक पहुंच सकती है।

इसलिए, अगर हम 'डिमांड में कमी' (जो अभी लगभग 5 मिलियन बैरल प्रति दिन है और भविष्य में और बढ़ सकती है) और कीमतों की वजह से सप्लाई में बढ़ोतरी (जो लगभग 8 से 9 मिलियन बैरल प्रति दिन है) के मिले–जुले असर को देखें, तो यह कुल मिलाकर लगभग 13–14 मिलियन बैरल प्रति दिन बैठता है; और भू–राजनीतिक कारणों ने युद्ध के सबसे अशांत दिनों में भी, स्ट्रेट ऑफ़ होर्मुज़ के लगातार बंद रहने के बावजूद, कच्चे तेल की कीमत को +100 प्रति बैरल के आसपास बनाए रखने में अहम भूमिका निभाई थी। अब जब स्ट्रेट ऑफ़ होर्मुज़ खुल गया है, तो अचानक कीमत गिरकर सिर्फ़ 70 डॉलर प्रति बैरल हो गई है और आने वाले दिनों में यह और गिर सकती है। 'डिमांड में कमी' और 'अतिरिक्त सप्लाई' के मिले–जुले असर का नतीजा यह है कि युद्ध खत्म होने के तुरंत बाद कच्चे तेल की कीमतें तेजी से गिरकर 70 डॉलर प्रति बैरल पर आ गई हैं और ये 50 से 60 डॉलर प्रति बैरल के बीच कहीं भी और नीचे जा सकती हैं। यह ट्रेंड तेल के अर्थशास्त्र को प्रभावित कर सकता है, लेकिन भारत के लिए निश्चित रूप से 'अच्छी खबर' है।

❑ ❑ ❑

MSMEs & ESG Reporting: Compliance to Competitiveness

Insights
Jayanti Goela
CEO, Gaslab Asia
National Coordinator-
LUB's Net-Zero Aayam
IICA Certified ESG Professional
(Impact Leader) Member, NAIL
Jgoela@ssgaslab.com

Bharat's MSMEs have always practised sustainability in their own way: by conserving resources, standing by workers, honouring commitments, and running businesses with integrity. Today, the world calls this ESG - Environment, Social and Governance. For us, it is not a new philosophy; it is an old value system that now needs to be measured, organised, and communicated.

When many MSME owners hear the words 'sustainability report', their first reaction is hesitation. It sounds like a mountain of paperwork, complex global frameworks, and another compliance burden. The concern is understandable.

The experience of manufacturers across the world, and increasingly in India, points to a different truth. Done sensibly, sustainability reporting is a pathway to competitiveness, not a compliance burden. Most MSMEs already possess the data needed to begin: electricity bills, water logs, production records, ESI and PF challans, GST filings, statutory returns, pollution compliance records, waste-disposal receipts, customer audits and vendor ledgers. What is needed is simply organise the data, understand what it tells us, and use it for better decisions. *This is the journey from compliance to competitiveness.*

The World is Moving in This Direction

Across supply chains, small enterprises are being asked for sustainability information by buyers, banks and large companies. Europe's voluntary sustainability reporting standard for non-listed SMEs is deliberately modular, so smaller businesses can report what is relevant to their business without carrying full corporate-reporting weight. This principle matters for Bharat: start with what is material to your business, not with every possible ESG indicator.

A textile unit may begin with energy, water, effluent, worker safety and statutory compliance. An engineering unit may begin with electricity intensity, consumables, scrap, worker retention, safety and customer audit records. A food-processing unit may focus on cold-chain energy, water, packaging waste, hygiene and traceability.

The indicators differ; the approach is the same.

The fear is often larger than the exercise itself. In Germany, small units that began by simply compiling electricity bills, production logs and operating data discovered avoidable energy losses and improved efficiency. In Italy, studies of small food and furniture manufacturers found that many were already practising sustainability through worker welfare, waste management and responsible supplier relationships - they had simply never called it ESG.

Many MSMEs are already practising sustainability, but because the information sits in separate files, it is invisible to buyers, bankers and even to the owner. ESG reporting brings the existing facts onto one page and turns them into management insight.

Our Own Experience

Let me share what happened when we did this in our own unit.

We manufacture pressure vessels and carbon-capture systems, exporting to the Middle East, Europe and Korea. As exporters, the news around CBAM and other sustainability-linked trade measures pushed us to compile our existing environmental, social and governance data into a simple sustainability report.

Some findings were uncomfortable. Power consumption per unit of output was higher than we had assumed. Consumables were higher than expected. Paper use through job cards, drawings and inspection records was significant and entirely unmeasured. We had never treated it as waste; it was simply 'how we operated'. Once the data was placed together, the inefficiencies became visible.

The Social data told another story we had never properly shared. We discovered high worker retention and a long-standing commitment to supporting the education of workers' children. We had been doing this quietly for years without thinking of it as reportable.

That honest two-page baseline data changed three things. First, it gave us an improvement roadmap. Two years later, we are almost paperless, and our power and consumables are measurably lower. We improved because the data made the issue visible. Second, it helped us enter the supply chain of a global buyer we had not been able to access earlier. The buyer did not ask for a glossy report; it asked for credible data, and we had it. Third, it opened a green-finance conversation with banks for expansion that would not have happened without data on paper.

If this can work for an engineering unit in Delhi NCR, it can work for a fabric-processing unit in Bhilwara, a packaging unit in Faridabad, a foundry in Rajkot, a food-processing unit in Indore or a component manufacturer in Coimbatore. The metrics will differ; the principle is identical.

The Data is Already There

Every month, MSMEs generate valuable ESG data without realising it. Electricity bills show energy consumption. Water meters show water intensity. Production records show output. ESI and EPFO challans show statutory worker coverage. Factory Act returns show safety and employment data. Pollution compliance files show waste, effluent and emissions. Accounts ledgers show vendor payment discipline. GST and tax filings show governance regularity.

This data already exists in our files. Scattered, it does nothing for us. Organised, it can reduce cost, improve productivity, strengthen buyer confidence, support bank discussions and prepare us for supply-chain requirements.

What a Baseline Can Look Like

Consider Unit A, a fabric-processing unit in Bhilwara with 40 workers and 15 years in business, recently shortlisted as vendor by a garment exporter in Jaipur supplying European brands. The owner of Unit A spends one hour compiling a Year 1 baseline.

❑ ❑ ❑

LUB's Chhattisgarh IIF Update

LUB's Chhattisgarh is organizing its flagship program, the 'India Industrial Fair' (IIF), in the state for the first time. Consequently, the IIF team is visiting various industrial areas and organizational units to provide comprehensive information about the event. On June 13, State President Smt. Sipi Dubey, General Secretary Shri Pranjal Thakur, and Bhilai Women's Wing President Smt. Rashmi Verma visited the Bhatapara, Bilaspur, and Janjgir units. Smt. Dubey noted that industrial units and entrepreneurs are showing great enthusiasm in associating with this event.

How TAMIL NADU can Achieve One Trillion-Dollar Economy with MSME Sector…

Wide Angle
Jayakumar Venkataraman
Former State Gen. Secretary, LUB Tamil Nadu
qtechproducts@gmail.com

Tamil Nadu, one of the country's most progressive and industrially developed states, aims to become a one-trillion-dollar economy by 2030. Undoubtedly, this requires the state's new government to build a fresh industrial ecosystem- an initiative for which the entrepreneurs of the state have high expectations of the newly elected Chief Minister, Shri C. Joseph Vijay.

The state boasts a strong manufacturing base, with many units exporting textiles, textile machinery, valves, auto components, and other engineering parts. Many of the micro-manufacturing units are either ancillaries to bigger industries or suppliers of components to medium and large-scale units. Recently, the GSDP of the State reached around ₹36 Lakh Crore of which 54% service sector, 33% manufacturing, and 13% agriculture. But the Agriculture sector remaining the largest employer.

Tamil Nadu is a front runner in MSME schemes such as below apart from PMEGP…

- **NEEDS (New Entrepreneur cum Enterprise Development Scheme):** Provides a 25% capital subsidy (with defined state caps) and interest subvention on term loans for setting up new manufacturing or service projects.
- **UYEGP (Unemployed Youth Employment Generation Program):** Focuses on micro-enterprises in both manufacturing (up to ₹50 lakhs) and services (up to ₹20 lakhs). It offers a localized subsidy ranging from 15% to 35% based on urban/rural areas and social categories.
- **AABCS (The Annal Ambedkar Business Champions Scheme)** offers a 35% capital subsidy (up to ₹1.5 Crore) and a 6% interest discount to support SC/ST entrepreneurs in starting or expanding manufacturing and service businesses.

The Tamil Nadu Single Window Portal (TNSWP) integrates 200+ services across 30 departments to provide clearances. The change needed is to give a onetime query to stop back-and-forth delays, If delayed Deemed Approvals to be provided.

1. Inclusive Growth

To achieve inclusive growth and become a one-trillion-dollar economy, it is of the utmost importance to augment the income of rural youth and ensure they get gainful employment in their own villages without abandoning agriculture.

During LUB's National AGM, RSS Sah-Sarkaryavah Shri Krishna Gopal ji stated: "Hundreds of townships garner benefits that should have been spread over thousands of villages." Only then will inclusive growth be achieved and reverse migration take place.

Here, some policy-based barriers are mentioned that keep rural Tamil Nadu and its youth backward:

- **Uninterrupted Power Supply in Rural Areas:** MSMEs set up in rural Tamil Nadu are given power supply through rural feeders, which means they do not get continuous three-phase supply in villages. Even if a person wants to start a micro-

manufacturing unit, he must migrate to the nearest town or district headquarter. This hampers rural development.

- **Physical Connectivity:** The Central Government deserves thanks for providing excellent digital connectivity in every village, whereas physical connectivity is not even satisfactory yet. This is because the government does not allow the operation of share autos in rural areas. The villages get public transport connectivity only once in the morning and once in the evening, which hampers the movement of agricultural produce to and fro.

2. The Village Cluster Model:

To reverse migration, the Government should introduce an alternate, decentralized industrial model:

- **Strategic Land Allocation:** Mandate that 5% to

10% of land in every village (capped at a maximum of 50 acres per village) be reserved strictly for industrial development.
- **Natural Ancillary Clusters:** Once a major anchor unit (such as a Drone Manufacturing Facility, an Automotive Assembly Plant, EV, or Defense) settles in a village, its ancillary units will be set up in adjoining villages, evolving a natural cluster.
- **Incentives:** Provide Tax holidays and robust infrastructure incentives to anchor unit and their ancillary MSME units that establish operations in these designated rural areas.

If infrastructure incentives-such as the benefits given to SEZs-are granted to units moving to rural blocks, India will entirely eliminate economically backward blocks within a decade. Large manufacturers will actively look forward to these affordable rural hubs. This model successfully echoes past localized industrial booms, such as Pondicherry's declaration as a backward district, industrial rollouts in Himachal Pradesh and Uttarakhand. This allows rural youth to significantly augment their household income without abandoning agriculture.

3. Utilization of MSMEs for National Growth

"*Necessity is the mother of invention*".

During the pandemic, PPE kits were not readily available; hence, textile manufacturing units in Tirupur started manufacturing PPEs and exporting them globally.

Similarly, now that the trans-shipment of produce faces challenges, alternate ways may be found to utilize these setups for Defense procurement-such as manufacturing all-weather garments or using machining facilities to manufacture components and sub-parts. Likewise, many heavy fabrication units located in and around Tiruchirappalli (Trichy) can be utilized for railway wagon manufacturing.

Auto Ancillary units are there in Chennai, Hosur, Coimbatore & Pondicherry region which can be utilized for defense sub parts and aero parts.

Due to recent scrappage policy, many Heavy Vehicles Body Building units in Karur, Villupuram will get affected so they can be utilized for Container Manufacturing.

4. Labor Shortage:

Tamil Nadu is one of the major employment giver for Migration Workers. With recent development happening in Northern States, most of the Migrants are going back to their home. Also, Students coming out after education are not Industry Ready.

Need urgent intervention from State Government in addressing the issues:

- Address the skill gaps by providing training and making them employable.
- Apprenticeship benefits are utilized by corporates, need special schemes exclusively for MSME to attract employees.
- Need to allow youth to start working from the age of 16 as many at this age are becoming prey for anti-social elements.

5. GST for Micro-Units

Introduction of GST has created a level playing field for everyone. GST Reforms are welcomed for reducing Automobile GST 28% to 18% which boosted the Industrial Output. When GST was rolled out, taxation for almost all segments was revenue-neutral except for micro-manufacturing units and job workers.

In fact, these micro-manufacturing units were not registered under excise during the VAT regime. They were paying only VAT, and the excise component was paid by their buyers under the Reverse Charge Mechanism (RCM). Currently, the entire GST portion-which includes the conversion cost-is borne by the seller, which has increased the tax liability and the outflow of cash working capital by 251% (as illustrated below).

Sale value	Paid by Micro Units	Paid by Buyer on RCM	Revenue to Government	Total	% Increase in Cash Outflow
Before GST (VAT Regime)					
100	5 (5%)	13 (12.5%)	18	118	
After GST					
100	18 (18%)	0	18	118	251%*

**Cash burden on Micro Manufacturing Units & Job Workers.*

Our Suggestions:

- For all B2B transactions, the buyer should be made to pay the tax directly to the government. The seller can then claim their input tax credit from their next month's purchase. This creates a win-win situation for all businesses, reduces the possibility of mismatches, and saves burden for GST officials. Since GST is a destination-based tax.
- Alternatively, fix a flat GST rate of **5%** for all B2B transactions.

6. Environmental and Civic Considerations: The Chennai Airport Case-

The proposed Greenfield Airport at Parandur near Chennai threatens to destroy vital lakes and occupies thousands of acres of agricultural land, which will create local opposition and long-term environmental degradation. Greenfield airports are best suited for land-locked regions.

For coastal states like Tamil Nadu, the Government must look toward **Bluefield Offshore Airport Models**- similar to those implemented successfully in Bangkok and Japan. Utilizing coastal geography prevents the displacement of farming communities. It is welcome that the new government is reconsidering this decision. With the declaration of intent by the State Government to work in unison with the Central Government on developmental issues, we are certain that Tamil Nadu will achieve its target of a one-trillion-dollar economy easily by 2030.

❑ ❑ ❑

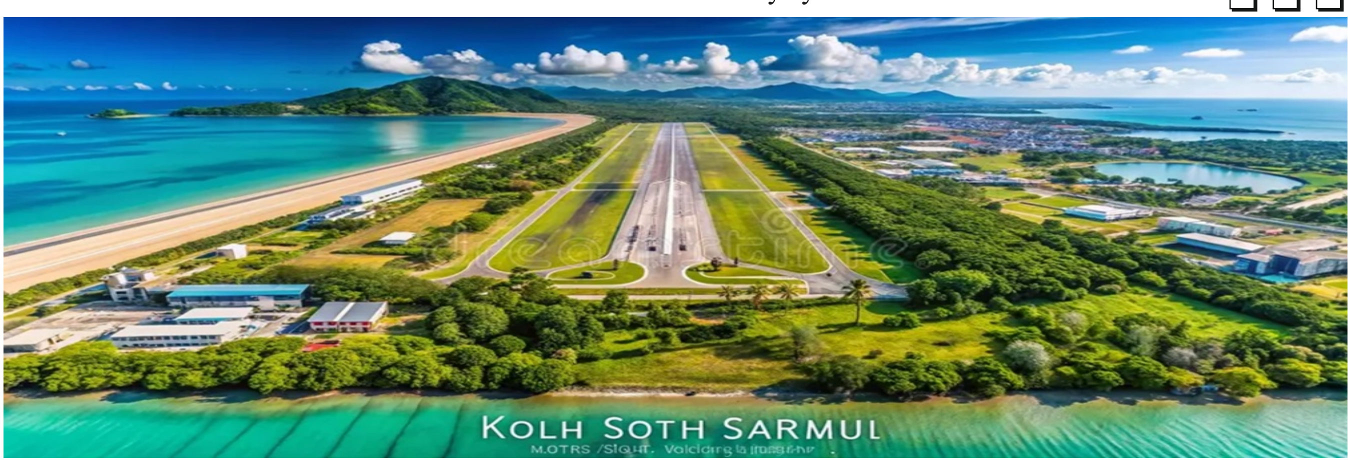

LAGHU UDYOG BHARATI, CHANDIGARH

साइकिल का वो सफर,
जिसने भर दी सैकड़ों परिवारों के जीवन में खुशहाली और सुगंध

उद्यम यात्रा
परवीन परगाल गुप्ता
अग्रणी उद्यमी एवं प्रभारी,
जम्मू एंड कश्मीर, लघु उद्योग भारती
pargalgroup@gmail.com

हर सफल उद्यमी की कहानी में ऐसे संघर्ष भी शामिल होते हैं, जिनसे वो रात–दिन गुजरा, वे सपने जिन्हें पूरा करने की जिद में उसने अपनी इच्छाओं को पीछे छोड़ दिया। ऐसी ही प्रेरणादायक कहानी है श्री परवीन गुप्ता की। आज उनका नाम जम्मू–कश्मीर के प्रमुख उद्यमियों में लिया जाता है। उनके उत्पाद जम्मू–कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और पंजाब तक अपनी पहचान बना चुके हैं। उनके उद्योग से सैकड़ों परिवारों का घर चलता है। लेकिन इस सफलता के पीछे छिपा है बरसों का संघर्ष, अथक परिश्रम और अडिग विश्वास।

पिता का सपना, जिसने पूरे परिवार की दिशा बदल दी

श्री परवीन का जन्म जम्मू–कश्मीर के आरएस पुरा क्षेत्र के रतिया गांव में हुआ। उनके पिता स्वर्गीय श्री दर्शन कुमार परगाल गांव में एक छोटी–सी किराना दुकान चलाते थे। आय सीमित थी, लेकिन सपने बहुत बड़े थे। वे चाहते थे कि उनके चारों बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त करें और जीवन में उन अवसरों तक पहुँचें, जो उन्हें स्वयं कभी नहीं मिल पाए।

इसी सोच के साथ वर्ष 1977 में उन्होंने एक साहसिक निर्णय लिया। उन्होंने गांव छोड़कर पूरे परिवार के साथ जम्मू शहर में बसने का फैसला किया। उस समय परवीन केवल चौथी कक्षा में पढ़ते थे। यह निर्णय आसान नहीं था। गांव की अपनी पहचान, अपना घर और अपना परिवेश छोड़ना किसी भी परिवार के लिए कठिन होता है। लेकिन एक पिता के लिए बच्चों का भविष्य सबसे बड़ा होता है।

अमर उजाला ग्रुप की ओर से जम्मू में आयोजित एमएसएमई कॉन्क्लेव में विशेष सम्मान प्राप्त करते हुए श्री परगल।

आर्थिक संघर्षों के बीच शुरू हुआ जीवन का असली पाठ

जम्मू आने के बाद भी परिस्थितियाँ आसान नहीं हुईं। परिवार की आर्थिक स्थिति लगातार संघर्षपूर्ण रही। श्री दर्शन परगाल ने कई छोटे–छोटे व्यवसाय शुरू किए। कभी सब्ज़ी का काम किया, कभी अन्य व्यापार करने का प्रयास किया।

आखिरकार उन्होंने एक ऐसा काम शुरू किया जिसमें वे फैक्ट्रियों और थोक व्यापारियों से नमकीन, मिश्रण और अन्य खाद्य सामग्री लेकर छोटे दुकानदारों तक सप्लाई करने लगे। यही व्यवसाय आगे चलकर पूरे परिवार की पहचान बनने वाला था।

जब बचपन ने जिम्मेदारियाँ ओढ़ लीं

परवीन ने बहुत छोटी उम्र से ही अपने पिता का हाथ बँटाना शुरू कर दिया था। छठी–सातवीं कक्षा में पढ़ते–पढ़ते वे व्यापार की बारीकियाँ सीखने लगे। समय के साथ पिता का स्वास्थ्य कमजोर रहने लगा। घर में सबसे बड़े होने के कारण परवीन जी ने बिना किसी शिकायत के जिम्मेदारियाँ अपने कंधों पर उठा लीं। दसवीं कक्षा तक पहुँचते–पहुँचते वे स्वयं मार्केटिंग और सप्लाई का बड़ा हिस्सा संभालने लगे।

पढ़ाई भी... और जिम्मेदारी भी

परवीन ने कभी शिक्षा और जिम्मेदारियों को एक–दूसरे का विकल्प नहीं बनने दिया। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की और आगे चलकर बी. कॉम. की पढ़ाई भी की। दिन में कॉलेज और बाकी समय व्यापार–यही उनकी दिनचर्या बन गई थी।

जहाँ अधिकांश विद्यार्थी घर से जेब खर्च लेकर कॉलेज आते थे, वहीं परवीन अपनी मेहनत से कमाते थे। कई बार तो वे अपने मित्रों के चाय–नाश्ते का खर्च भी स्वयं उठा लिया करते थे। कॉलेज में अधिकांश लोग उन्हें एक सम्पन्न परिवार का युवक समझते थे। उन्हें लगता था कि परवीन पहले से ही एक सफल व्यवसायी परिवार से हैं। लेकिन बहुत कम लोग जानते थे कि उन्हीं कपड़ों में कॉलेज आने वाला यह युवक कुछ देर पहले गांव–गांव घूमकर दुकानों तक सामान पहुँचाकर आया होता था।

यदि कभी कोई सहपाठी उन्हें काम करते हुए देख लेता, तो वे नज़रें चुरा लेते थे। उन्हें अपने काम से कभी शर्म नहीं थी, लेकिन वे नहीं चाहते थे कि कोई उनकी मजबूरियों को गलत नजर से देखे। आज वही संघर्ष उनकी सबसे बड़ी पहचान बन चुका है।

साइकिल बनी सफलता की पहली गाड़ी

परवीन जम्मू से लगभग 10 से 12 किलोमीटर दूर उन क्षेत्रों तक माल लेकर जाते थे जहाँ उनकी सबसे अधिक सप्लाई होती थी। वहाँ पहुँचकर वे अपने दिन का पूरा रूट तय करते और फिर साइकिल पर अलग–अलग गांवों और बाजारों में जाकर दुकानदारों तक सामान पहुँचाते।

एक दुकान...फिर दूसरी...फिर तीसरी... और इसी तरह पूरा दिन ग्राहकों के बीच गुजरता। उनके लिए हर ग्राहक केवल ग्राहक नहीं था, बल्कि विश्वास का एक रिश्ता भी था।

जब तवी नदी भी नहीं रोक सकी रास्ता

संघर्ष केवल दूरी का नहीं था। बरसात के दिनों में तवी नदी उफान पर होती थी। कई बार बसें आगे नहीं जा पाती थीं। ऐसे समय में परवीन अपना सामान सिर पर रखकर नंगे पाँव नदी पार करते, फिर वापस आकर अपनी साइकिल दूसरी ओर ले जाते और आगे की यात्रा जारी रखते। उनके लिए कठिनाइयाँ कभी रुकने का कारण नहीं बनीं। वे जानते थे कि यदि ग्राहक तक समय पर माल नहीं पहुँचेगा, तो उसका विश्वास टूट जाएगा। और व्यापार की सबसे बड़ी पूँजी विश्वास ही होता है।

एक अधूरा सपना

ग्यारहवीं और बारहवीं के दौरान पढ़ाई में उनकी विशेष रुचि बढ़ी। उन्होंने निश्चय किया कि वे चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) बनेंगे। उन्होंने इसके लिए तैयारी भी शुरू की। लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति, पिता का स्वास्थ्य और सबसे बड़े बेटे की जिम्मेदारी उनके सामने खड़ी थी। उन्होंने अपने सपने को त्याग दिया... लेकिन कभी शिकायत नहीं की। क्योंकि उनके लिए उस समय परिवार का भविष्य, उनके अपने कॅरियर से बड़ा था।

1984 – वह दिन जिसने सोच बदल दी

वर्ष 1984 में एक दिन उन्होंने पहली बार 1,000 रुपये की कमाई की। उस समय यह केवल एक राशि नहीं थी। यह उनके आत्मविश्वास की पहली कमाई थी।

उसी दिन उन्होंने मन में ठान लिया–'अब मैं केवल दूसरों का सामान नहीं बेचूँगा, अपना उद्योग खड़ा करूँगा।'

10,000 रुपये की कमेटी और करोड़ों के सपनों की शुरुआत

व्यवसाय शुरू करने के लिए पूँजी की आवश्यकता थी। बैंक से ऋण लेना आसान नहीं था। तब उन्होंने अपने परिवार–चाचा–चाची, मामा और अन्य रिश्तेदारों– के साथ 500 रुपये प्रति सदस्य की एक कमेटी शुरू की। कुल 20 सदस्य थे। हर महीने 10,000 रुपये की कमेटी बनती थी। पहली कमेटी स्वयं उठाकर उन्होंने अपने जीवन का सबसे बड़ा निर्णय लिया। उन्होंने अपने घर की छत पर ही अपना उद्योग शुरू करने का निश्चय किया।

घर की छत पर जन्मा एक उद्योग

कमेटी से मिले पैसों से उन्होंने टीन का एक छोटा–सा शेड बनवाया। अपने मौसा जी के साथ पंजाब जाकर लगभग 2,000 रुपये की एक डीज़ल भट्ठी खरीदी। उस समय जम्मू–कश्मीर में आतंकवाद का दौर था। बाहर जाकर मशीन खरीदना, कच्चा माल लाना और व्यापार करना अपने आप में एक चुनौती था। लेकिन परवीन ने कभी डर को अपने निर्णयों पर हावी नहीं होने दिया। घर की छत पर नमकीन और मिश्रण बनना शुरू हुआ। शुरुआत छोटी थी...लेकिन इरादे बहुत बड़े थे।

बाजार की समझ बनी सबसे बड़ी ताकत

वर्षों तक बाजार में काम करने के कारण वे ग्राहकों की जरूरतों को अच्छी तरह समझ चुके थे। वे जानते थे कि दुकानदार किस गुणवत्ता का सामान चाहते हैं। यही अनुभव उनकी सबसे बड़ी पूँजी बना। पहले जिन व्यापारियों तक वे दूसरों का माल पहुँचाते थे, अब वही व्यापारी उनके अपने उत्पाद खरीदने लगे। सिर्फ एक वर्ष के भीतर उनका उत्पादन कुछ किलो से बढ़कर लगभग दस क्विंटल प्रतिदिन पहुँच गया। यह किसी चमत्कार से नहीं, बल्कि वर्षों की मेहनत, ईमानदारी और ग्राहकों के विश्वास का परिणाम था।

छत से फैक्ट्री तक का सफर

उत्पादन बढ़ा। दूसरी भट्ठी लगी। फिर उन्होंने लगभग तीन लाख रुपये में आधा एकड़ भूमि खरीदी। यहीं से उनके उद्योग ने एक नई उड़ान भरी। जो उद्योग कभी घर की छत पर शुरू हुआ था, वह अब एक व्यवस्थित फैक्ट्री में बदल चुका था। घर की छत पर लगभग दस लोगों को रोजगार मिलता था।

फैक्ट्री बनने के बाद यह संख्या बढ़कर 100 से 150 कर्मचारियों तक पहुँच गई।

उद्योग नहीं... एक परिवार की पहचान

समय के साथ उन्होंने केवल नमकीन तक अपने व्यवसाय को सीमित नहीं रखा। उन्होंने कन्फेक्शनरी उत्पाद जोड़े। फिर पैकेज्ड मिठाइयों का निर्माण शुरू किया। गुणवत्ता और विश्वास उनकी सबसे बड़ी पहचान बन गए। आज उनके उत्पाद जम्मू–कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और पंजाब के हजारों दुकानों तक पहुँचते हैं। लेकिन उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि केवल व्यापार का विस्तार नहीं है।

उन्होंने इस व्यवसाय को अपने पूरे परिवार का व्यवसाय बनाया। उन्होंने अपने भाइयों को साथ लेकर चलना चुना। आज सभी भाई एकजुट होकर उसी उद्योग को आगे बढ़ा रहे हैं, जिसकी नींव कभी घर की छत पर रखी गई थी। यही एक सच्चे परिवार की सबसे बड़ी ताकत होती है– साथ चलना, साथ बढ़ना और साथ सफल होना।

संघर्ष का सबसे सुंदर परिणाम

आज जब लोग श्री परवीन को एक सफल उद्योगपति के रूप में देखते हैं, तो उन्हें विशाल फैक्ट्री, स्थापित ब्रांड और सफल व्यवसाय दिखाई देता है। लेकिन उस सफलता के पीछे छिपा वह किशोर बहुत कम लोगों को दिखाई देता है– जो साइकिल पर गांव–गांव सामान पहुँचाता था...जो पढ़ाई और काम दोनों साथ लेकर चलता था...जो अपने सपनों से पहले अपने परिवार को रखता था...और जिसने कभी परिस्थितियों को अपनी मंज़िल से बड़ा नहीं बनने दिया।

युवाओं के लिए संदेश

श्री परवीन की जीवन यात्रा हमें सिखाती है कि सफलता विरासत में नहीं मिलती, उसे अपने पसीने से अर्जित करना पड़ता है। यदि नीयत साफ हो, मेहनत ईमानदार हो, परिवार साथ हो और लक्ष्य स्पष्ट हो, तो एक साधारण साइकिल से शुरू हुआ सफर भी एक दिन सैकड़ों लोगों के जीवन में रोजगार, सम्मान और उम्मीद का कारण बन सकता है।

यही है श्री परवीन की कहानी–एक ऐसे कर्मयोगी की कहानी जिसने संघर्षों को सीढ़ी बनाया, परिवार को अपनी ताकत बनाया और अपने सपनों को समाज की खुशहाली से जोड़ दिया।

❑ ❑ ❑

- उद्योग टाइम्स के को–एडिटर
  डॉ.संजय मिश्रा से बातचीत पर आधारित

LUB Gujarat Felicitates 101 Women Entrepreneurs *with* 'Business Woman Excellence Award'

On the occasion of the 33rd Foundation Day of Laghu Udyog Bharati, the Rajkot Women's Wing organized a magnificent 'Business Woman Excellence Award' ceremony. During this event, 101 progressive women entrepreneurs from the city were encouraged and honored with mementos for their outstanding contributions.

On this occasion, an inspiring address was given by Smt. Anjaliben Rupani (Wife of Late Former CM Shri Vijaybhai Rupani and Former In-charge of Mahila Morcha). Appreciating the potential of women, she stated, "In today's era, women are capable of excelling in every field; they simply need the right platform, which is being effectively provided by Laghu Udyog Bharati."

LUB's Former National President Dr. Baldevbhai Prajapati provided detailed insights into the working methodology of Laghu Udyog Bharati.

Former Mayors Smt. Rakshaben Boliya and Smt. Nayanaben Pedhadiya also urged women to take advantage of various government schemes to become economically self-reliant.

Dr. Pinnaa Kotak, President of Rajkot Women's Wing, informed about the organization's upcoming programs.

Ms. Artiben Prajapati (Gujarat State Women President) praised the multitasking skills of women, noting that achieving success in business while managing family responsibilities is a matter of great pride.

Shri Hansrajbhai Gajera provided guidance and best wishes to women entrepreneurs for taking their businesses to a global level.

In collaboration with CED (Centre for Entrepreneurship Development), Coordinator Smt. Komalben remained present and provided expert guidance regarding professional business training.

The entire program was successfully anchored by Dr.

Shivani Kotak. The event's success was made possible by the dedicated efforts of the Laghu Udyog Bharati Women's Wing office bearers, including Dr. Trupti Kotak Raja, Smt. Alkaben Kamdar, Smt. Hinaben Raval, Smt. Jayshreeben Vyas, Smt. Sudhaben, Smt. Brindaben Patel, and Smt. Nishaben Cholera.

❑ ❑ ❑

दूरदर्शिता और सकारात्मक सोच ने साकार की सफलता इंटर सोलर की

उद्यम यात्रा
देविंदर कौशल
अग्रणी उद्यमी एवं सदस्य– लघु उद्योग भारती
पार्टनर– इंटर सोलर सिस्टम्स प्रा. लि. पंजाब
dk@intersolarsystems.com

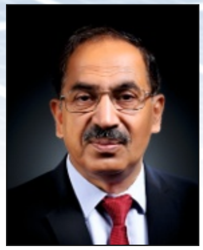

उद्यम यात्रा
भूपिंदर कुमार
अग्रणी उद्यमी एवं सदस्य– लघु उद्योग भारती
पार्टनर– इंटर सोलर सिस्टम्स प्रा. लि. पंजाब
bk@intersolarsystems.com

इंटर सोलर की स्थापना 1997 में एक स्पष्ट दूरदृष्टि के साथ की गई थी– साफ़–सुथरे, हरे–भरे और टिकाऊ भविष्य के लिए सौर ऊर्जा की शक्ति का इस्तेमाल करना। उस समय जब भारत में रिन्यूएबल एनर्जी (नवीकरणीय ऊर्जा) की शुरुआत हो ही रही थी, तब भी हमें पूरा भरोसा था कि सौर ऊर्जा ही भविष्य का ऊर्जा स्रोत बनेगी। हमारा मिशन हमेशा से भरोसेमंद और प्रदूषण–मुक्त ऊर्जा समाधान देना रहा है, जो लोगों की ज़िंदगी को बेहतर बनाए और साथ ही आने वाली पीढ़ियों के लिए पर्यावरण की रक्षा भी करे।

मिडिल क्लास मानसिकता और नौकरी

मेरा जन्म हिमाचल प्रदेश के ऊना में मध्यमवर्गीय परिवार में हुआ। मेरे माता–पिता दोनों ही नौकरी पेशा थे। तो स्कूलिंग के बाद ही ये तय हो चुका था कि आगे की पढाई करके मुझे भी नौकरी करनी है। इसलिए कैमिकल इंजीनियरिंग में बीई की डिग्री पूरी की और वर्ष 1987 में नॉर्थ इंडिया की सोलर कंपनी को ज्वॉइन किया फैक्ट्री मैनेजर के पद पर। यहीं पर दो वर्ष बाद 1989 में मेरी मुलाक़ात भूपिंदर कुमार से हुई जो सेल्स मैनेजर की पोजीशन पर काम करते थे। दोनों ही ग्रामीण क्षेत्रों और समान आर्थिक पृष्ठभूमि से भी जुड़े थे, तो काम करते–करते सहज ही हमारी मित्रता हुई। भूपिंदर ने सोलर एनर्जी में डै.ब. की डिग्री की थी। और इस तरह से हम दोनों मित्रों को ही सोलर इंडस्ट्री की तकनीक और वर्किंग का अच्छा अनुभव और ज्ञान हो गया।

ऐसे पड़ा उद्यमिता का बीज

हमने देखा कि भारत में सोलर एनर्जी की भरपूर संभावना है। देश के हर हिस्से में रोज़ाना 5 KWH/m^2 सोलर एनर्जी मिलती है, जो एक सस्टेनेबल एनर्जी है। उसके बावजूद 1990 के दशक तक उत्तर भारत में सोलर एनर्जी प्रोडक्ट्स बनाने वाली कोई भरोसेमंद कंपनी नहीं थी। इसलिए हमें लगा कि यही सही समय है और आखिरकार हमने वर्ष 1997 में हम दो डायरेक्टर्स ने पार्टनरशिप फर्म के रूप में चंडीगढ़ में सोलर एनर्जी कंपनी को शुरू करने का निर्णय लिया। कंपनी एक छोटी–सी किराए की फैक्ट्री में सिर्फ़ दो कर्मचारियों के साथ शुरू की। शुरुआती समय बहुत चुनौतियों से भरा था। सौर ऊर्जा के बारे में लोगों में जागरूकता की कमी तो थी ही, इसके साथ ही ग्राहकों का भरोसा जीतने के लिए भी लगातार कोशिश करनी पड़ती थी।

शुरुआत छोटी– संघर्ष बड़ा

इंटर सोलर की कहानी लगन, कड़ी मेहनत और अपने विज़न के प्रति अटूट प्रतिबद्धता का सबूत है। उस समय पूंजी की कमी एक चुनौती थी क्योंकि हमने 3 लाख रुपये की छोटी पूंजी से शुरुआत की। उस समय की कई बढ़ती हुई कंपनियों की तरह ही, हमें भी भारी आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा। गिरवी रखने के लिए कोई संपत्ति (कोलेटरल सिक्योरिटी) न होने के कारण विस्तार के लिए बैंक से फ़ाइनेंस मिलना मुश्किल था। उस दौर में ब्याज दरें भी बहुत ज़्यादा (12% से 15%) थीं। इसलिए हमने अपनी कम पूंजी से ही धीरे–धीरे काम किया। हां, दोस्तों व रिश्तेदारों से कुछ पैसे भी हमने उधार जरूर ले लिए बिना ब्याज के।

कंपनी के पास आर्थिक संसाधन बहुत सीमित थे। हम रॉ–मटेरियल लाने के लिए ऑटो–रिक्शा का खर्च भी नहीं उठा सकते थे, इसलिए हम लोकल मार्केट से सामान लाने के लिए अपने टू–व्हीलर का ही ज्यादातर इस्तेमाल करते थे। इंस्टॉलेशन के काम के लिए, हम उसी गाड़ी पर वेल्डिंग

का सामान भी कस्टमर की साइट तक ले जाते थे। यहाँ तक कि लैंडलाइन टेलीफ़ोन भी एक बड़ी लग्ज़री थी, जिसके लिए 2 साल से ज़्यादा का इंतज़ार करना पड़ता था। इसलिए ग्राहकों से फ़ॉलो–अप के लिए हमने पेजर और ज्व दोनों की मदद ली। हमने BIS के लिए अप्लाई किया, लेकिन कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि हमारी यूनिट बहुत छोटी थी। इन मुश्किलों के बावजूद, हम क्वालिटी वाले प्रोडक्ट और भरोसेमंद सर्विस देने के लिए प्रतिबद्ध रहे।

सोलर के लिए स्पष्ट विजन रखा

शुरुआती दौर में भारत सरकार ने सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी शुरू की जो करीब 90 फीसद तक चली गई

केंद्रीय मंत्री महिला एवं बाल विकास श्रीमती अन्नपूर्णा देवी से मेक इन इंडिया लीजेंड्स फॉर सोलर मैन्युफैक्चरिंग एक्सीलेंस अवॉर्ड प्राप्त करते हुए डेप्युटी डायरेक्टर श्री अखिल कौशल

थी। सरकार का उद्देश्य तो योजना को घर–घर तक पहुँचाना था, लेकिन अधिकारीयों और बिचोलियों ने मिलकर सब्सिडी का खेल कर दिया। परिणाम ये हुआ कि ख़राब गुणवत्ता के उपकरणों ने इस योजना को पूरी तरह नकारात्मक बना दिया। और फिर वर्ष 1995 भी आया, जब भारत सरकार ने सारी सब्सिडी को बंद कर दिया। सोलर में काम करने वाले बहुत से वेंडर्स ये मानते थे कि बिना सब्सिडी तो सोलर का कोई भविष्य ही नहीं है, और इसे कोई नहीं खरीदेगा। लेकिन इस फैसले ने सोलर एनर्जी के लिए हमारे भाव को और दृढ कर दिया। हमें मालूम था कि असली ग्रोथ स्टोरी तो अब शुरू होने वाली है, और वही हुआ भी। भारत में आज 200 से अधिक कंपनियां सोलर पैनल्स और इक्विपमेंट्स निर्माण का कार्य कर रही है।

और जब जागी उम्मीद

वर्ष 2007 में एक बड़ा मोड़ आया, जब भारत सरकार की 'माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज़ के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट' (CGTMSE) स्कीम ने हमें बिना पारंपरिक संपत्ति को गिरवी रखे इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस हासिल करने में बड़ी मदद की। और बेहद नाजुक समय में मिली इस वित्तीय सहायता ने हमारी ग्रोथ को निश्चित रूप से तेज़ किया और हमारी मैन्युफैक्चरिंग क्षमताओं को भी पहले की तुलना में और मजबूत कर दिया।

क्वालिटी मैन्युफैक्चरिंग से बनी बाजार में जगह

हमारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लैस हैं, जिससे हम ऐसे इनोवेटिव, एनर्जी–एफिशिएंट और टिकाऊ प्रोडक्ट बना पाते हैं जो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर की बदलती

जरूरतों को पूरा करते हैं। आज, इंटर सोलर एडवांस्ड रिन्यूएबल एनर्जी समाधानों की एक प्रमुख मैन्युफ़ैक्चरर बन गई है, जो क्वालिटी, क्षमता और परफॉर्मेंस के सबसे ऊँचे मानकों को पूरा करने वाले प्रोडक्ट देती है। हमारे प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की रेंज दो वर्टिकल में बंटी है–

1. हाई–परफॉर्मेंस सोलर फोटोवोल्टिक (PV) पैनल एवं सोलर पावर प्लांट वगैरह

2. हीट पंप एवं सोलर वाटर हीटिंग सिस्टम

- मोनो PERC 550 W मॉड्यूल
- TOP Con बायफेशियल N- टाइप मॉड्यूल
- 600 W और 720 W सोलर च्ट मॉड्यूल
- 10,000 लीटर तक के स्टेनलेस स्टील स्टोरेज टैंक
- घरों, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और इंस्टीट्यूशनल इस्तेमाल के लिए कस्टमाइज़्ड रिन्यूएबल एनर्जी सॉल्यूशन

कंपनी बनी भरोसेमंद इंडस्ट्री लीडर

हमारी सेल्स स्ट्रेटजी के मुताबिक हम लगभग 100 संभावित ग्राहकों से संपर्क करते थे, लेकिन उनमें से केवल दो ही ऑर्डर हमें मिल पाते थे। हर ग्राहक को हमने हमारे समर्पण, लगातार कोशिश और क्वालिटी के प्रति प्रतिबद्धता से हासिल किया। लगभग तीन दशकों में, इंटर सोलर ने क्वालिटी प्रोडक्ट, टेक्नोलॉजी में इनोवेशन और भरोसेमंद आफ्टर–सेल्स सर्विस के ज़रिए ग्राहकों का भरोसा जीता है। आज, हमारे साथ लगभग 180 समर्पित प्रोफेशनल काम करते हैं जो बेहतरीन सर्विस और ग्राहकों की संतुष्टि के हमारे वादे को पूरा करने के लिए मिलकर काम करते हैं। एक मज़बूत टीम और इंडस्ट्री के बड़े अनुभव के साथ, हमने पूरे भारत में 5 लाख से ज़्यादा ग्राहकों को सफलतापूर्वक सर्विस

चंडीगढ़ गवर्नर श्री गुलाब चंद कटारिया से पंजाब, हरियाणा एवं चंडीगढ़ क्षेत्र में 'पीएम सूर्य घर योजना' के तहत सबसे ज़्यादा सोलर पावर प्लांट लगाने के लिए इंटर सोलर सिस्टम्स की टीम सम्मान प्राप्त करते हुए

दी है, जिनमें होटल और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, अस्पताल और हेल्थकेयर संस्थान, शिक्षण संस्थान और यूनिवर्सिटी, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़, कमर्शियल बिल्डिंग्स, सरकारी संगठन, घर और हाउसिंग सोसाइटी, इंफ्रास्ट्रक्चर और पब्लिक यूटिलिटी प्रोजेक्ट्स।

सफल होने का जज़्बा जरूरी

ग्राहकों के भरोसे, हमारे कर्मचारियों के समर्पण और रिन्यूएबल एनर्जी में इनोवेशन की हमारी लगातार कोशिशों का सुपरिणाम ये रहा कि पहले वर्ष में जहां इंटर सोलर का टर्नओवर सिर्फ़ ₹4.5 लाख था, वो FY 25-26 में 82 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। ये 160 लोगों को सीधे और 55 लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोज़गार देता है।

सोलर इंडस्ट्री – चुनौती भी और संभावनाएं भी

सोलर इंडस्ट्री की सबसे बड़ी चुनौती है उसकी टेक्नोलॉजी जो हर 4–5 वर्षों में बदलती रहती है। इसी तरह से सोलर एनर्जी से जुड़ी सरकारी नीतियां भी बहुत अस्थिर रही हैं सब्सिडी मिलने में भी कई बार महीनों और बरसों लग जाते थे और कभी–कभी तो अचानक से सब्सिडी बंद भी हो जाती थी। जहां तक इस उद्योग के भविष्य का सवाल है, तो निश्चित तौर पर वो उम्मीद जगाने वाला है। सोलर एनर्जी में संभावनाएं असीमित हैं। भारत में प्रति व्यक्ति सोलर एनर्जी इंस्टॉलेशन सिर्फ़ 70 वॉट है, जबकि हमारे प्रतिस्पर्धी पड़ोसी देश चीन में यह 700 वाट प्रति व्यक्ति है। वहीं ऑस्ट्रेलिया में 180 KWH प्रति व्यक्ति सोलर इंस्टॉलेशन है। अभी भारत में सिर्फ़ 0.003% घरों में सोलर पावर सिस्टम लगे हैं।

उसके बावजूद हम चीन को प्रतिस्पर्धा में पीछे नहीं धकेल पाए। चाइनीज पैनल और दूसरे इक्विपमेंट्स से लागत स्पर्धा भारत के उद्यमी नहीं कर सकते। हालात ये हैं कि जब चीन

जाने–माने अभिनेता और निर्माता श्री जिमी शेरगिल से MY FM एलीट क्लब एक्सीलेंस अवार्ड्स–2026 प्राप्त करते हुए उप–निदेशक श्री अखिल कौशल और उप–निदेशक श्री प्रशांत मारवाह

से आयात होने वाले सोलर कंपोनेंट्स पर भारत सरकार ने 47 प्रतिशत ड्यूटी और 1 रुपया फ्रेट लगा दिया, उसके बाद भी चीनी उत्पाद सस्ते ही रहते। चीनी सोलर सिस्टम पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए भारत सरकार ने वर्ष 2023 में सौर ऊर्जा क्षेत्र में प्रचलित मॉडल और निर्माताओं की अधिकृत एवं अनुमोदित सूची–एएलएमएम (Approved List of Models and Manufacturers) जारी की, तब जाकर मेक इन इंडिया मुहीम को बल मिला।

आगे की राह........नयी पीढ़ी के साथ

दो कर्मचारियों वाली एक छोटी किराए की फैक्ट्री से लेकर लगभग 180 कर्मचारियों और पाँच लाख से ज़्यादा ग्राहकों वाली एक सम्मानित कंपनी बनने तक, इंटर सोलर का सफ़र विज़न, लगन और लगातार इनोवेशन की ताकत को दिखाता है। सोलर इंडस्ट्री में अब हमारी दूसरी पीढ़ी भी साथ आ गई; अखिल कौशल 10 वर्षों से और प्रशांत मारवाह 7 वर्षों से कंपनी को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं।

जैसे–जैसे दुनिया साफ़ और सस्टेनेबल एनर्जी की ओर बढ़ रही है, कंपनी भी सोलर टेक्नोलॉजी के साथ मैन्युफैक्चरिंग क्षमता को बढ़ाने और भरोसेमंद रिन्यूएबल एनर्जी सॉल्यूशन देने के लिए प्रतिबद्ध है, जिससे भारत की एनर्जी जरूरतों के साथ ग्रीन सस्टेनेबल फ्यूचर में भी अपना योगदान कर सकें।

❑ ❑ ❑

- लघु उद्योग भारती, पंजाब के प्रदेश अध्यक्ष श्री प्रदीप मोंगिया से बातचीत पर आधारित।

LUB's Gujarat General Secretary Shri Hansraj Bhai Gajera participated as Panelist in the important Session on Import substitute for Atmanirbhar Bharat with former Finance & Revenue Secretary, GoI Shri Hasmukh Bhai Adhiya-IAS and Joint Secretary, Ministry of Commerce, GoI Shri Ajay Bhadu in Vibrant Gujarat Regional Conference conducted at Vadodara on 29-30 June, 2026.

LUB's Gujarat State General Secretary Shri Hansraj Bhai Gajera participated as Panelist in the Session on Atmanirbhar Bharat in Defence Manufacturing with Chief of DRDO Shri Rajesh Kumar Singh in Vibrant Gujarat Regional Conference conducted at Vadodara on 29-30 June, 2026.

Laghu Udyog Bharati participated in the First BRICS MSME Forum and Third SME Working Group Meeting held in Agra on 19th June. LUB's National Jt. GS Shri Rakesh Garg, National Treasurer Shri Mahesh Gupta, National Secretary Shri Deepak Agarwal, UP General Secretary Shri Amit Agarwal and Jt. GS Shri Gaurav Mittal attended the same.

नौकरी लेने नहीं, देने की सोचें .... तो जीवन में तरक्की करेंगे

उद्यम यात्रा
राकेश आर. अग्रवाल
वरिष्ठ उद्यमी एवं सोल प्रोप्राइटर –
टेक्नो इंडस्ट्रीज, चंडीगढ़
संरक्षक– लघु उद्योग भारती, चंडीगढ़ इकाई
nfolenterprises@hotmail.com

पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ से 1977 में केमिकल इंजीनियरिंग (B.Tech.) की पढ़ाई पूरी करने के बाद कैंपस प्लेसमेंट में मुझे नौकरी मिली बल्लारपुर इंडस्ट्रीज पेपर मिल, यमुनानगर (हरियाणा) में। लगभग 2 वर्ष वहां बतौर असिस्टेंट इंजीनियर कार्य किया। पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से उन दिनों कुछ युवाओं ने इंजीनियरिंग करने के बाद चंडीगढ़ और मोहाली में अपनी औद्योगिक इकाइयां शुरू की थीं, साथ ही स्माल इंडस्ट्री सर्विस इंस्टीट्यूट, लुधियाना ने भी एक सेमीनार आयोजित किया था जिसने मेरी सोच को ही बदल दिया था। बस, वहीं से प्रेरणा लेकर मैंने भी 1979 में नौकरी छोड़कर अपनी इकाई स्थापित करने का फैसला ले लिया।

जब एक बार निर्णय ले लिया, तो ले लिया, फिर तो आगे बढ़ना था और ये भी तय करना था कि उद्योग कौनसा स्थापित करना है। उद्योग शुरू करने के लिए बहुत बड़ी पूँजी थी नहीं घर पर। और फिर पिताजी भी नौकरी में होने की वजह से कोई विशेष मदद नहीं कर सके थे। तो मैंने मित्रों से सलाह की और इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट के कुछ चक्कर भी काटने के बाद जिंक सल्फेट, जो की एक क्रॉप माइक्रोन्यूट्रिएंट है, की इकाई लगाने का निर्णय लिया।

मैंने इधर–उधर से कुल मिलाकर 50 रु. हजार का बंदोबस्त किया और 2 लाख रुपए का ऋण दिल्ली फाइनेंशियल कॉरपोरेशन (DFC) से लेना तय किया। लेकिन इस सारी भागदौड़ में मेरा पहली बार ही सरकारी नौकरशाही से काम पड़ा। एसएसआई रजिस्ट्रेशन से लेकर लोन लेने तक कोई चक्कर कटा रहा था, तो कोई रिश्वत लेना चाह रहा था।

लेकिन उनको इस बात का कोई मलाल, कोई अंदाजा शायद नहीं था कि उनके सूबे का 24 साल का युवा इंजीनियर उनके घटिया व्यवहार से कितना आहत हुआ होगा, जो नौकरी छोड़ कर वहां उद्योग लगाने आया था।

आखिर कर्ज उठाकर उस इकाई को एक किराए के शेड में वर्ष 1980 में चालू किया। इससे पहले पुनः मैंने अपने निर्णय पर अंतिम बार मनन किया, लेकिन नौकरी न कर अपना काम करने के जज्बे ने मुझे बहुत मजबूत बना दिया था और धीरे–धीरे मैं आगे बढ़ना शुरू हो गया।

सबसे पहले जिंक सल्फेट को बनाने का रॉ मैटेरियल, जो की जिंक एश थी उसे बाहर से इंपोर्ट करने का काम शुरू किया क्योंकि यह एक नॉनफ़ेर्रोस मेटल स्क्रैप था तो इंपोर्ट में इसके साथ जुड़ती हुई कॉपर और एल्युमिनियम की स्क्रैप भी मंगवानी शुरू कर दी।

फिर कॉपर की स्क्रैप को भी एक और यूनिट लगाकर तार में बदलना शुरू किया और एल्युमिनियम की स्क्रैप को रोल लेवल और कांस्टेबल इन गाटस में बदलने के काम ने भी गति पकड़ी। प्रभु कृपा और बड़ों के आशीर्वाद से काफी उन्नति हुई इस काम में।

वर्ष 1995 में एक बार फिर दिशा बदली और अपने काम में राइस ब्रान तेल की रिफाइनिंग का काम भी जोड़ दिया और रिफायनिंग के बाद बचे हुए तेल से सिट्रिक एसिड बनाना शुरू किया जिससे वर्ष 2005 तक दो बड़ी इकाइयां इसी

काम को करने लगी। इसी दौरान जिंक ऑक्साइड बनाने की एक इकाई विराटनगर–नेपाल में भी स्थापित की। लेकिन वो तो समय का हेर–फेर कहें और कुछ सरकारी नीतियों का बदलाव भी, उसी वर्ष में भारी नुकसान उठाकर मुझे दोनों इकाइयों को बंद करने के लिए मजबूर होना पड़ा।

इस सब उलटफेर के करीब एक वर्ष के अंतराल के बाद अपनी पुरानी जिम्मेदारियों से निवृत्त होकर फिर से उद्योग

का काम शुरू कर दिया।

अब सीलिंग फैन की मोटर का निर्माण कर रहा हूं और एक छोटा कास्ट आयरन का यूनिट भी चल रहा है और जितना समय निकलता है उसमें विभिन्न संस्थाओं में अपने अर्जित किए हुए अनुभव को साझा कर उद्योग जगत की सेवा करने का प्रयत्न कर रहा हूं।

मैं पढ़े–लिखे नौजवानों से यही आग्रह करता हूँ कि वे नौकरियों की तरफ ना भागे। वे अपने व्यापार से न केवल अपने आप को सम्पन्न करे, बल्कि समाज में अन्य युवाओं को भी कुछ नई नौकरियां देने का काम करें।

वर्तमान में मेरी कंपनी का टर्नओवर भले ही 7–8 करोड़ ही है, लेकिन संतोष इस बात का भी है कि मेरी लघु इकाई जैसी बहुत–सी इकाइयां मिलकर मेरे देश और प्रदेश की इकॉनमी में अच्छा योगदान कर रही हैं और रोजगार सृजन भी। मेरी कंपनी में 50 कर्मचारी काम करते हैं।

मैं इस बात को पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि यह कोई अधिक कठिन कार्य नहीं है इसमें केवल लगन और मेहनत की ही जरूरत है। इसके साथ–साथ अपनी जरूरत को कम रखने से आपकी सफलता सुनिश्चित होती है और तीव्र भी।

- लघु उद्योग भारती, चंडीगढ़ (यूटी) के महासचिव श्री मनीष निगम से बातचीत पर आधारित।

❑ ❑ ❑

During a visit to Patiala, Shri Dipen Kamra-Jt. Secretary Patiala unit-presented a memorandum regarding the challenges faced by various industries to National Org. Secretary Shri Prakash Chandra Ji on 13th June. On the occasion, National VP Shri Arvind Dhumal, Co-Incharge North Region Shri Shubh Aadesh Mittal, North Zone Media In-charge Shri Vikrant Sharma, Punjab State President Shri Pradeep Mongia, Jt. GS Shri Anil Sharma, Jt. Treasurer Shri Suresh Gupta, In-charge Harish Gupta, Patiala Unit President Shri Arun Kumar, and General Secretary Shri Manu Bhardwaj were present. Shri Sarvadaman Bharat expressed vote of thanks.

देवभूमि पर संघर्ष, संकल्प और सफलता की उद्यमिता यात्रा

उद्यम यात्रा

दीपक गोयल

प्रबंध साझेदार– सुशिमा लैबोरेट्रीज, रूद्रपुर
सदस्य, लघु उद्योग भारती उत्तराखंड
sushimalab23@yahoo.co.in

उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर पिलखुवा में मेरा जन्म 22 दिसंबर, 1968 को हुआ था। पिता पेशे से डॉक्टर थे और माता गृहिणी। लेकिन मेरे दादा एवं पूर्वज अनाज के व्यापार से जुड़े हुए थे। वैसे हमारा परिवार तो साधारण ही था, लेकिन पारिवारिक संस्कारों और नैतिक मूल्यों ने मेरे व्यक्तित्व को प्रारम्भ से ही मजबूत आधार प्रदान किया।

माता–पिता ने बहुत संघर्ष और मेहनत करके हम तीनों भाई–बहनों को शिक्षित किया। हम मां की आँखों में हमारे लिए हमेशा बड़े सपने और उम्मीदें देखते हुए बड़े हुए थे। यही प्रेरणा हमें जीवन में कुछ बड़ा करने के लिए आगे बढ़ाती रही। इसी भावना के साथ मैंने अपने भाई के साथ मिलकर अपने घर से ही पशुओं की दवाओं की एक छोटी–सी दुकान शुरू की।

अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद, 1991 में हमने गाजियाबाद के दवा बाजार में पशुओं की दवाओं की थोक दुकान शुरू की। पहले ही साल में हमने 36 लाख रुपये का टर्नओवर हासिल किया। उस समय हमारे पास सिर्फ 2 कर्मचारी ही थे। वे आम तौर पर पूरे दिन दवाओं की सप्लाई करने और पेमेंट इकट्ठा करने के लिए हम दोनों भाइयों में से किसी एक के साथ स्कूटर पर जाते थे जिस पर दवाओं के कार्टन भी लदे होते थे और दूसरा भाई दुकान पर ग्राहकों को संभालने का काम करता।

दुकान शुरू हुए अभी अधिक समय भी नहीं हुआ था कि हमारे जीवन में एक बहुत ही कठिन दौर आया जब हमें मां को कैंसर होने का पता चला। उनके इलाज में हमने अपनी पूरी क्षमता से, अपने सारे पैसा लगा दिए, लेकिन दुर्भाग्यवश वर्ष 1992 में उनका निधन हो गया। इस घटना ने हमारे जीवन की दिशा ही बदल दी। इसके बाद हमने दुनियादारी को लगभग त्याग ही दिया और अपना पूरा ध्यान और समय वापस अपनी थोक की दुकान पर ही लगा दिया।

जब 10–12 वर्ष में हमारी थोक दुकान से अच्छा प्रतिसाद मिलने लगा, तब खुद की पशुओं की दवाओं की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट (उत्पादन इकाई) लगाने का बीज मन में कहीं गहरे प्रस्फुटित हुआ। और वर्ष 2005 में, वो समय भी आया। ईश्वर ने हमें अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने का रास्ता दिखाया और हमने 'देवभूमि' उत्तराखंड में कदम रखा। शुरुआत में हमने सोचा था कि हम 800–900 मीटर का सबसे छोटा प्लॉट ले लेंगे, और उसके लिए आवेदन भी कर दिया था। लेकिन फिर किसी ने हमें सलाह दी कि दवाओं की यूनिट लगाने के लिए ये प्लॉट छोटा पड़ेगा। तब हमने बड़े प्लॉट के लिए आवेदन किया, लेकिन जो प्लॉट हमें आवंटित हुआ था, वो बिजली विभाग में तब्दील होना था। यहाँ पर सरकार ने हमारा सहयोग किया और हमें उस प्लॉट के बदले, एक प्राइम लोकेशन पर प्लॉट अलॉट कर दिया।

उत्तराखंड सरकार द्वारा प्रदत्त
'उत्तराखंड राज्य स्मॉल इंडस्ट्रीज़ अवॉर्ड–2012
मुख्यमंत्री श्री हरीश रावत से प्राप्त करते हुए

ET-RE फार्मा अवार्ड्स 2026 में 'वेटरनरी फार्मा कंपनी ऑफ द ईयर' प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त करते हुए

वर्ष 2007 में, आखिरकार हमारी यूनिट मैन्युफैक्चरिंग शुरू करने के लिए तैयार हो गई। हमने इस यूनिट का नाम अपनी माताजी की याद में रखा, उनका नाम 'सुशीला' था, इसलिए यूनिट का नाम 'सुशि मा' रखा। यह मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हमारे खानदान की पहली यूनिट थी। इसके लिए हमें पहली बार गाजियाबाद स्थित एक मात्र अचल संपत्ति अपने घर को गिरवी रखकर 65 लाख रुपये का बैंकलोन लेना पड़ा। ये हमारी जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण फैसला था क्योंकि वही घर हमारी सब से बड़ी पूंजी थी। मन में कहीं ये डर तो था ही कि कहीं जो हमने सोचा है, वैसा यदि नहीं हुआ, तो हम अपनी इकलौती छत भी खो सकते हैं। लेकिन ईश्वर की कृपा, हमारे साथ काम करने वाले लोगों के सहयोग और मेहनत की बदौलत हमने पहले ही साल में 1.70 करोड़ रुपये का टर्नओवर हासिल कर लिया। कारोबार लगातार बढ़ता गया और हम 5 वर्षों के लिए लिया गया पूरा बैंक लोन ब्याज सहित केवल 4 वर्षों में ही चुका दिया। आज कंपनी का टर्नओवर 50 करोड़ से नीचे जरूर है, लेकिन शीघ्र ही नए लक्ष्य तक पहुँचने में इसे पीछे छोड़ देंगे।

इसके बाद वर्ष 2011 में अपनी मौजूदा यूनिट के विस्तार के लिए फिर से बैंक लोन लिया। लेकिन उस समय हमें जो सब्सिडी सरकार से मिलनी चाहिए थी, वह किसी न किसी कारण से लगातार टलती रही और आज तक नहीं मिल सकी। फिर 2018 में निकट की एक यूनिट बिक रही थी जिसे अगले साल हमने लीज पर ले लिया। 2020 में कोरोना वायरस ने हमारे विस्तार की रफ़्तार पर ब्रेक लगा दिया; लेकिन वर्ष 2023 में नई दवा फैक्ट्री के अधिग्रहण के साथ कंपनी ने विकास की नई उड़ान प्रारम्भ की। अनुसंधान एवं विकास (R&D) पर विशेष ध्यान दिया ताकि पशु चिकित्सा क्षेत्र में उत्कृष्ट एवं विश्वसनीय उत्पाद उपलब्ध कराए जा सकें। दोनों ही अधिग्रहित प्लॉट को WHO-GMP दिशानिर्देशों के अनुसार विकसित करने के लिए भी बड़ा बैंक लोन लेना पड़ा।

हमें इस बात पर संतोष है कि हमारे बिजनेस में पार्टनर्स के साथ तालमेल और समझ में कभी समस्या नहीं आई, साथ ही हमारे परिवार ने भी चुनौतियों का सामना किया, हमारा साथ दिया। हमें समर्पित कर्मचारी भी मिले जो 20 बरसों से काम कर रहे हैं। हमने स्वस्थ औद्योगिक तौर–तरीकों को अपनाकर यहां रोजगार सृजन का कार्य किया जिसमें 70 फ़ीसदी कर्मचारी उत्तराखंड के ही रहने वाले हैं। कंपनी अब निर्यात और अन्य ऐसे क्षेत्रों की ओर कदम बढ़ाने के लिए उत्सुक है। बिजनेस में हमारी दूसरी पीढ़ी में बेटा चार्टर्ड अकाउंटेंट और भाई का बेटा वेटनरी डॉक्टर दोनों नयी पीढ़ी के पेशेवर जुड़ गए हैं जिससे संस्थान के विस्तार और विकास के लिए नया आत्मविश्वास जागा है।

कंपनी ने गुणवत्तापरक उत्पादों के निर्माण से GMP, GLP, ZED, ISO 9001:2015 सर्टिफिकेशन प्राप्त किये और ये सब उस समय हासिल किया जब हमें दवाइयों और मशीनरी के बारे में बहुत अधिक जानकारी नहीं थी। लेकिन अनुभव के साथ सीखते हुए हासिल किया। आज हमें दवा निर्माण और मशीनरी दोनों क्षेत्रों की अच्छी समझ है। शुरुआत में हमने मैनुअल मशीन लगाईं, फिर सेमी–ऑटोमेटिक मशीनों की ओर बढ़े और बाद में फुल ऑटोमेटिक मशीनों पर शिफ्ट हो

रहे हैं। अब नए ब्लॉक में एडवांस मशीनें लगा कर ब्लॉक को WHO-GMP प्रमाणन प्राप्त करने के उद्देश्य से विकसित किया जा रहा है। भविष्य के लिए कंपनी का लक्ष्य केवल व्यवसाय विस्तार तक सीमित नहीं है, बल्कि वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान स्थापित करना, निर्यात क्षेत्र में मजबूती से प्रवेश करना तथा अनुसंधान एवं नवाचार के माध्यम से उद्योग को नई दिशा देना है।

उत्तराखंड की प्राकृतिक सुंदरता, स्वच्छ वातावरण, औद्योगिक अनुकूल नीतियाँ और बेहतर आधारभूत संरचना ने भी इस विकास यात्रा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विशेष रूप से SIDCUL जैसे औद्योगिक क्षेत्रों के विकास ने राज्य को उद्योग एवं निवेश का प्रमुख केंद्र बनाने में अहम योगदान दिया है।

❑ ❑ ❑

लघु उद्योग भारती, उत्तराखंड प्रदेश के रुड़की जिला महामंत्री श्री वीरेंद्र शुक्ल से बातचीत पर आधारित।

Shri Hansrajbhai Gajera, State General Secretary of Laghu Udyog Bharati (Gujarat), paid a courtesy call on Union Defence Minister Shri Rajnath Singh during the recently held 'Vibrant Gujarat' event at Vadodara and requested the establishment of a defence corridor, defence PSUs, and DRDO facilities in Gujarat to support MSMEs.

Laghu Udyog Bharati-Panipat (Haryana) organized an entrepreneurs' conference on 10th June. Speaking on the topic 'MSME: Current Scenario, Challenges, and Long-term Solutions' National Org. Secretary Shri Prakash Chandra ji emphasized the vital importance of understanding India's industrial and economic evolution from the past to the present. He noted that the country began its development journey from virtually zero after independence, following the plunder by foreign invaders; yet today, India stands among the world's top economies and is advancing towards self-reliance across various industrial sectors. All that is required is firm determination and consistency.

National Vice President Shri Arvind Dhumal highlighted LUB's contribution to industrial development. AIWC member Shri Shubh Aadesh Mittal urged industrialists to bring their issues to the attention of the organization.

Haryana State President Shri Raman Saluja remarked that every industry has its own unique characteristics and challenges; therefore, the active participation and engagement of units from every district are essential.

Prominent industrialist Shri Bhim Rana and State General Secretary Manoj Rangta, along with other entrepreneurs, attended the event. The proceedings were conducted by Shri Kapil Gupta, President LUB Panipat unit.

उद्यमिता में संघर्ष, संस्कार और सफलता का सुन्दर समन्वय

उद्यम यात्रा

गौतम चौधरी

MD वीएनएम ग्रुप, हरियाणा

सदस्य लघु उद्योग भारती, हरियाणा

gc.vnmpl@gmail.com

कभी पंजाब के बठिंडा में पढ़ाई करने वाले एक साधारण से युवक ने अपनी इंजीनियरिंग पूरी कर एस्कॉर्ट ट्रैक्टर (फोर्ड) कंपनी में नौकरी की...वही आज सैकड़ों लोगों को रोजगार देने वाला सफल उद्योगपति है। संयुक्त परिवार का आदर्श प्रस्तुत करने के साथ उद्यमी श्री गौतम चौधरी ने समाजसेवी के रूप में भी अपनी विशेष पहचान बनाई। उनकी सफलता में संस्कार, संघर्ष, परिवार, शिक्षा और स्वदेशी सोच की प्रेरक गाथा नई पीढ़ी को श्रेष्ठ मार्ग दिखाती है।

गौतम ने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई बठिंडा में पूरी की। इसके बाद उन्होंने 1984 में पटियाला के थापर इंजीनियरिंग कॉलेज से बीई मैकेनिकल की डिग्री हासिल की। पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने फरीदाबाद स्थित एस्कॉर्ट ट्रैक्टर लिमिटेड (फोर्ड) में नौकरी शुरू की। करीब 10 वर्षों तक नौकरी के दौरान उन्होंने उद्योग जगत की तकनीक, गुणवत्ता और प्रबंधन को करीब से समझा।

फिर आया वर्ष 1994 जब उन्होंने अच्छी–भली चल रही नौकरी को छोड़कर अपने बड़े भाई श्री वी. एस. चौधरी के साथ व्यवसाय में कदम रखा जिन्होंने 1989 में ही फरीदाबाद में अपना उद्योग स्थापित कर लिया था। उस समय बल्लभगढ़ के मलेरना रोड पर छोटी–सी फैक्ट्री से काम शुरू किया था। व्यवसाय की शुरुआत एक ऐसे रबर उत्पाद डैम्पिंग वॉशर से हुई, जिसे उस समय विदेशों से आयात किया जाता था। दोनों भाइयों ने तकनीकी ज्ञान, नवाचार और मेहनत के दम पर इस आयातित उत्पाद को स्वदेशी रूप में तैयार कर दिया। यहीं से वीएनएम इंडस्ट्रीज की रबर उद्योग में मजबूत शुरुआत हुई थी।

धीरे–धीरे कंपनी टेलीकॉम सेक्टर के लिए रबर उत्पाद बनाने वाली कंपनियों की सप्लायर बनी और बाद में ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी अपनी पहचान बनाई। पांच कर्मचारियों से शुरू हुई यह स्माल स्केल यूनिट आज 300 से अधिक लोगों को रोजगार दे रही है। वीएनएम ग्रुप ऑफ़ इंडस्ट्रीज के आज दो प्लांट फरीदाबाद और दो हरिद्वार में संचालित हैं। कंपनी IATF 16949, ISO 9001, ISO 14001 प्रमाणित है और गुणवत्ता आधारित उत्पादन के लिए जानी जाती है।

उद्योग जगत में उल्लेखनीय योगदान के लिए गौतम चौधरी को कई सम्मान मिले। वर्ष 2007 में तत्कालीन केंद्रीय लघु उद्योग मंत्री श्री प्रेमचंद गुप्ता ने उन्हें स्वनिर्भर उद्योग में उल्लेखनीय कार्य के लिए उद्योग–मित्र सम्मान से सम्मानित किया। वर्ष 2023 में यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड ने उन्हें डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान की। इसके अलावा द इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स इंडिया भी उन्हें इंजीनियरिंग क्षेत्र में बेहतर योगदान के लिए सम्मानित कर चुकी है।

उनका नाम CII की बुक 'हॉल ऑफ इंडिया' में भी दर्ज है। श्री चौधरी सामाजिक और धार्मिक कार्यों में भी लगातार सक्रिय रहे हैं। वर्ष 2000 में रोटरी इंटरनेशनल से जुड़कर उन्होंने समाज हित में कई कार्य किए। मानव सेवा समिति में विभिन्न ज़िम्मेदारियां निभाईं। वर्तमान में वे राजस्थान एसोसिएशन फरीदाबाद के अध्यक्ष हैं। करीब 20 वर्षों से लघु उद्योग भारती से जुड़े हैं और इस समय फरीदाबाद इकाई में वरिष्ठ उपाध्यक्ष के दायित्व पर कार्य कर रहे हैं।

इसके अलावा वे फरीदाबाद इंडस्ट्रीज एसोसिएशन में एग्जीक्यूटिव मेंबर, मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन फरीदाबाद, आईएमटी इंडस्ट्रीज एसोसिएशन फरीदाबाद, फरीदाबाद चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री तथा इंडस्ट्रियल वेलफेयर एसोसिएशन सेक्टर–58 में भी विभिन्न पदों पर सक्रिय हैं।

श्री चौधरी की सफलता की नींव उस पारिवारिक वातावरण में पड़ी, जहां शिक्षा, संस्कार और पारिवारिक एकता को सर्वोच्च महत्व दिया जाता था। उनके पिता स्व. श्री पन्नालाल चौधरी जी दूरदर्शी सोच वाले उद्यमी थे, जिन्होंने वर्ष 1940 में अपना व्यवसाय शुरू किया और अपने सभी बच्चों को उच्च शिक्षा दिलाने का सपना देखा। माता श्रीमती जमोत्री चौधरी धार्मिक प्रवृत्ति की थीं और उन्होंने परिवार में नैतिक मूल्यों व संस्कारों की मजबूत आधारशिला रखी।

परिवार में शिक्षा का स्तर हमेशा प्रेरणादायी रहा। सबसे बड़े भाई स्व. डॉ. पी.सी. चौधरी सवाई माधोपुर के प्रतिष्ठित चिकित्सकों में गिने जाते थे, जबकि दूसरे भाई श्री बी.के. चौधरी ने वर्ष 1970 में गोल्ड मेडलिस्ट एमबीए बनकर परिवार का नाम रोशन किया। छह भाइयों में सबसे छोटे गौतम ने भी इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए अपने परिश्रम, अनुशासन और दूरदृष्टि से उद्योग जगत में अलग पहचान बनाई।

संयुक्त परिवार की परंपरा आज भी इस परिवार की सबसे बड़ी ताकत है। गौतम और उनके बड़े भाई श्री वी.एस. चौधरी आज भी एक साथ संयुक्त परिवार में रहते हैं। दोनों परिवारों के बीच आपसी प्रेम, विश्वास और सामंजस्य समाज के लिए प्रेरणा माना जाता है। यही पारिवारिक एकता व्यवसाय में भी दिखाई देती है, जहां दोनों भाइयों ने कंधे से कंधा मिलाकर वीएनएम ग्रुप को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

उद्योग जगत में सफलता हासिल करने के साथ–साथ श्री गौतम ने सामाजिक जिम्मेदारियों को भी हमेशा प्राथमिकता दी। पर्यावरण संरक्षण, महिला सशक्तिकरण तथा जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे विषय उनके सामाजिक कार्यों के केंद्र में रहे हैं। उन्होंने विभिन्न सामाजिक संगठनों के साथ मिलकर कई जनहितकारी पहलें संचालित कीं। बल्लभगढ़ की चावला कॉलोनी में रोटरी क्लब के सहयोग से महिला सिलाई केंद्र की स्थापना कर अनेक महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने का अवसर दिया।

पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में भी उनका योगदान उल्लेखनीय रहा। रोटरी के साथ मिलकर कई स्थानों पर वृक्षारोपण से हरित क्षेत्र विकसित करने की पहल की। श्री गौतम मानते हैं कि उद्योग और समाज एक–दूसरे के पूरक हैं और किसी भी सफलता का वास्तविक अर्थ तभी है, जब उसका लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे।

शिक्षा को लेकर अपने माता पिता से मिली सीख का प्रभाव उनकी अगली पीढ़ी में भी दिखाई देता है। उनके बेटे डॉ. भानु चौधरी चिकित्सा क्षेत्र में अपनी पहचान बनाने के साथ अब व्यवसाय में भी सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। बहू डॉ. सोनाली चौधरी, बेटी डॉ. गरिमा चौधरी और दामाद डॉ. प्रशांत कटरे भी चिकित्सा क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य कर रहे हैं। संघर्ष, मेहनत, पारिवारिक मूल्यों और सामाजिक जिम्मेदारी के दम पर श्री गौतम उद्योग जगत में एक प्रेरक व्यक्तित्व बन चुके हैं।

❑ ❑ ❑

- लघु उद्योग भारती की राष्ट्रीय कार्यसमिति के सदस्य एवं हरियाणा प्रदेश प्रभारी श्री अरुण बजाज से बातचीत पर आधारित।

Historic Moment - LUB Form State Unit in Arunachal Pradesh

Laghu Udyog Bharati officially formed its Arunachal Pradesh Unit at Itanagar on 21st June. The inaugural ceremony was graced by Dr. Mohesh Chai, MLA cum Advisor to Minister of Industry, Govt. of Arunachal Pradesh, Shri Prakash Chandra ji- National Org. Secretary, Shri Om Prakash Gupta- National GS, Shri Partha Pratim Pathak- President Assam, Shri Kamlesh- RSS Prant Pracharak, Shri Hinium Takung- State Unit Convener and senior officials from various government departments, bankers and other institutions.

The program marked the official announcement of the newly appointed team for State Executive Committee: Shri Nima Sona- President, Shri Gollo Nyanya- Secretary and Mrs. Tage Rita- Treasurer.

On the occasion, the dignitaries emphasized that the establishment of the Arunachal Pradesh unit is a monumental step toward fostering a robust entrepreneurial ecosystem in the frontier state. Arunachal Pradesh's vast untapped potential in Handloom, Handicrafts, Agro-based industries, and local manufacturing is expected to receive a significant boost under the guidance of Laghu Udyog Bharati's national network.

लीक से हटकर काम करने का नाम ही है उद्यमिता

उद्यम यात्रा

रीता मित्तल

अग्रणी महिला उद्यमी

उपाध्यक्ष–लघु उद्योग भारती,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ

rtn.rita.mittal@gmail.com

परिस्थितियाँ इतिहास को नहीं लिखती, बल्कि इतिहास को वे लिखते हैं जो परिस्थितियों को भी बदलने का साहस रखते हैं। ऐसे ही आत्मविश्वास से लबरेज उत्तर प्रदेश ही नहीं, अलबत्ता भारत की प्रथम महिला मेंथॉल उद्यमी हैं श्रीमती रीता मित्तल। वे समाजसेवी, न्यायविद, महिला सशक्तिकरण एवं MSME सेक्टर की प्रेरक व्यक्तित्व भी हैं। वे कौशल विकास से महिलाओं को स्वावलंबी जीवन प्रदान करने के लिए पूरी शिद्दत से कार्य करना चाहती हैं। अपनी सफलता की कहानी से वे महिलाओं के साथ युवाओं और सभी वर्गों का ध्यान खींचती हैं। उनके जीवन पर आधारित एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी बनाई गई। श्रीमती मित्तल उद्योग, महिला सशक्तिकरण, उपभोक्ता अधिकार, MSME तथा सामाजिक विषयों पर अपने विचार मुखरता से रखती रही हैं।

मेरा जन्म उत्तर प्रदेश के रामपुर जनपद के एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ। बचपन से ही शिक्षा, अनुशासन, ईमानदारी और समाज के प्रति उत्तरदायित्व के संस्कार मेरे व्यक्तित्व का आधार बने। मैंने मनोविज्ञान में स्नातकोत्तर (M.A.) तथा विधि स्नातक (LL.B.) तक की शिक्षा प्राप्त की।

विवाह के बाद जीवन ने नई जिम्मेदारियाँ दीं। मेरे पति श्री उमेश कुमार मित्तल (IAS) प्रशासनिक सेवा में थे। मेरे मायके और ससुराल– दोनों परिवारों में अधिकांश लोग सरकारी सेवाओं से जुड़े थे। उद्योग या व्यापार का कोई अनुभव परिवार में किसी को नहीं था। ऐसे वातावरण में एक महिला का उद्योग स्थापित करने का सपना देखना भी असाधारण ही माना जाता था।

जब उद्योग लगाने का संकल्प मैंने खुद ही लिया, तो दोनों बच्चे बहुत छोटे थे, उस समय घर–गृहस्थी को भी पूरा समय देना जरूरी था। लेकिन एक ओर मातृत्व की जिम्मेदारी थी, दूसरी ओर मन ही मन में एक ऐसा सपना पल रहा था जो मुझे चैन से बैठने नहीं देता था। मैंने निश्चय किया कि यदि कुछ करना है, तो ऐसा करना है जिसे आज तक किसी महिला ने करने का साहस न किया हो।

एक विचार... जिसने इतिहास रच दिया

कई महीनों तक मैंने विभिन्न उद्योगों का अध्ययन किया। अंततः मेरी दृष्टि मेंथॉल उद्योग पर जाकर ठहरी। यह उद्योग पूरी तरह पुरुष–प्रधान था। किसानों से मेंथा ऑयल की खरीद, केमिकल प्रोसेसिंग, फैक्ट्री संचालन, बड़े वित्तीय निवेश और राष्ट्रीय–अंतरराष्ट्रीय व्यापार–इन सबको उस समय केवल पुरुषों का क्षेत्र माना जाता था। यहीं मैंने अपना निर्णय लिया कि यदि रास्ता कठिन है, तो वही मेरे लिए सही रास्ता है। और फिर वो क्षण भी आया जब वर्ष 1989 में मैंने Rum Aromatics Pvt. Ltd. की स्थापना की और उसकी Managing Director बनी।

लोगों की मानसिकता को बदला

कंपनी बन गई, उस पर काम भी शुरू कर दिया। मुझे अपने भीतर इस बात का गर्व भी था कि मैं पहली महिला उद्यमी के रूप में अपनी पहचान बनाने जा रही हूँ जो मेंथॉल फ्लेक्स एवं मेंथॉल क्रिस्टल की निर्माण यूनिट का संचालन करेगी।

लेकिन उस समय के उद्योग जगत के लोगों ने कहा कि यह महिलाओं का काम नहीं है, यह उद्योग महिलाओं के बस की बात नहीं है। इस तरह की आलोचनाओं को मैंने अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया और काम पर फोकस किया। मैं किसानों से मेंथा ऑयल की खरीद करती, फैक्ट्री का संचालन भी संभालती, बैंक और सरकारी विभागों के चक्कर लगाती, तकनीकी निर्णय लेती और साथ ही अपने छोटे बच्चों की परवरिश भी करती।

कई बार तो ऐसा भी होता था कि मीटिंग में लोग मेरे बजाय किसी पुरुष अधिकारी से बात करना चाहते थे, क्योंकि उन्हें विश्वास ही नहीं होता था कि एक महिला इतनी बड़ी केमिकल कंपनी की मालिक और निर्णयकर्ता हो सकती है। ये बात अलग है कि आगे चलकर वही लोग मेरे कार्य की सराहना भी करने लगे।

संघर्ष से सफलता तक

उद्योग की स्थापना के लिए मैंने उत्तर प्रदेश वित्त निगम (UPFC) से ऋण प्राप्त किया। उस समय उद्योग स्थापित करने की सरकारी प्रक्रियाएँ आज की तुलना में कहीं अधिक कठिन थीं। लाइसेंस, वित्तीय स्वीकृतियाँ, बिजली, प्रदूषण नियंत्रण, तकनीकी अनुमतियाँ–हर कदम एक परीक्षा ही तो थी। लेकिन मेरा विश्वास था कि हर कठिन लगने वाला कार्य अपने साथ सफलता का एक नया अवसर भी लेकर आता है।

Symbolic Image of Processing Unit of Menthol Oil

हम किसानों से मेंथा ऑयल लेकर उच्च गुणवत्ता वाले Menthol Crystals एवं Menthol Flakes (पुदीना सत्व', 'पुदीना कपूर' या 'पेपरमिंट कपूर) का निर्माण करते थे जो बहुत–सी दवाइयों, कॉस्मेटिक और अन्य उत्पादों में बहुत महत्वपूर्ण घटक के तौर पर काम आता है। हमारी लगभग सम्पूर्ण आपूर्ति निर्यातकों को होती थी, जो आगे विश्व के विभिन्न देशों में भारतीय उत्पाद पहुँचाते थे। विश्व में मेंथॉल उद्योग के दो प्रमुख केंद्र–भारत और चीन–माने जाते हैं। ऐसे महत्वपूर्ण उद्योग में एक महिला के रूप में आगे बढ़ना मेरे जीवन का सबसे गौरवपूर्ण अध्याय है। समय के साथ मेरे उद्योग ने लगभग 50 से 60 करोड़ रुपये के वार्षिक टर्नओवर का स्तर प्राप्त किया तथा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से बहुत से लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी सृजित किए। उद्योग संचालन के साथ–साथ मैंने कमोडिटी एवं स्टॉक मार्केट में भी सक्रिय रूप से कार्य किया, जिससे व्यापारिक दृष्टि और बाजार की समझ और अधिक परिपक्व हुई।

मेरे लिए उद्योग केवल व्यापार नहीं, राष्ट्र निर्माण का माध्यम है मैंने हमेशा माना कि उद्योगपति केवल अपने लिए नहीं, बल्कि समाज, किसानों, कर्मचारियों और राष्ट्र की आर्थिक प्रगति के लिए भी कार्य करता है। इसी सोच ने मुझे समाज सेवा की दिशा में भी निरंतर सक्रिय रखा।

उत्तर प्रदेश सरकार ने मुझे जिला उपभोक्ता आयोग का सदस्य नियुक्त किया, जहाँ लगभग पाँच वर्षों में 1500 से अधिक उपभोक्ता मामलों के निस्तारण का अवसर मिला। इसके पश्चात परिवार न्यायालय (Family Court) में आठ वर्षों तक सुलहकर्ता के रूप में कार्य करते हुए लगभग 500 परिवारों को टूटने से बचाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मेरे लिए यह सेवा किसी सम्मान से कम नहीं थी।

उद्योगों के लिए कार्य करने का अवसर मिला

उद्योग जगत से जुड़े अनुभवों के कारण मुझे MSME Facilitation Council का सदस्य बनाया गया, जहाँ उद्योगों के भुगतान संबंधी विवादों के समाधान में सक्रिय भूमिका निभाई।

इसी तरह लघु उद्योग भारती संगठन में भी प्रदेश स्तर पर दायित्व निभाते हुए मेरा प्रयास केवल संगठन का विस्तार करना नहीं, बल्कि एक ऐसा वातावरण बनाना रहा जहाँ प्रत्येक उद्यमी को मार्गदर्शन, सहयोग और आत्मविश्वास मिले। मेरा विश्वास है कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण केवल बड़े उद्योगों से नहीं, बल्कि लाखों छोटे और मध्यम उद्यमियों की सफलता से होगा।

महिला सशक्तिकरण – मेरा जीवन उद्देश्य

मैंने स्वयं उस क्षेत्र में सफलता प्राप्त की जिसे महिलाओं के लिए असंभव माना जाता था। इसलिए मेरा विश्वास है कि जब एक महिला आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनती है, तब केवल उसका जीवन नहीं बदलता, बल्कि पूरा परिवार, आने वाली पीढ़ियाँ और समाज बदल जाता है। इसी उद्देश्य से मैंने हजारों महिलाओं को कौशल विकास, स्वरोजगार, उद्यमिता और आत्मनिर्भरता की दिशा में प्रेरित किया। कितना अच्छा हो कि महिलाएं स्वयं को केवल नौकरी तक सीमित न रखे, बल्कि रोजगार देने वाली उद्यमी बने।

श्रीमती मित्तल को विभिन्न राष्ट्रीय एवं सामाजिक संस्थाओं द्वारा अनेक सम्मान एवं प्रशस्ति–पत्र प्राप्त हुए हैं। 'कमल शक्ति संवाद सम्मान', 'यूपी रत्न अवार्ड', अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस सम्मान तथा समाज सेवा के लिए पूर्व राज्यपालों द्वारा प्रदत्त सम्मान उनकी प्रतिबद्धता का प्रमाण हैं।

मेरा जीवन मंत्र

मेरा मानना है कि सफलता भाग्य से नहीं, साहस से मिलती है। सपने देखने वाले बहुत होते हैं, लेकिन उन्हें पूरा वही करते हैं जो संघर्ष से मित्रता कर लेते हैं। मैं चाहती हूँ कि हर बेटी यह विश्वास लेकर आगे बढ़े कि कोई भी क्षेत्र उसके लिए असंभव नहीं है। यदि आत्मविश्वास, ईमानदारी, परिश्रम और धैर्य साथ हों, तो मंज़िल स्वयं रास्ता बनाती है।

- उद्योग टाइम्स के को–एडिटर डॉ.संजय मिश्रा से बातचीत पर आधारित

❑ ❑ ❑

नमो नेतृत्व

अविस्मरणीय

अतुलनीय

अकल्पनीय

उद्योग टाइम्स के संग्रहणीय जुलाई अंक का प्रकाशन

देश के प्रधान सेवक की अनवरत यात्रा पर अपने मन की बात, विशेष सन्देश के साथ अपने प्रतिष्ठान / संस्थान / कंपनी का विज्ञापन भी विशेष दरों पर प्रकाशित करने का अवसर। आज ही अपनी कॉपी सुरक्षित करें। बल्क कॉपीज के लिए अग्रिम भुगतान करें।

Enquiry for Bulk Copies at
Laghu Udyog Bharati
Head Office, New Delhi - 8178921873
For Booking Special Messages & Advertisements-
edit.udyogtimes@gmail.com (9829558069)

Rajasthan Govt. made significant announcements on the International MSME Day

Chief Minister Shri Bhajanlal Sharma stated that Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) form the foundation of the state's economic progress, employment generation, and self-reliance. He addressed a gathering on International MSME Day at Jaipur on 27th June. He noted that, driven by government policies and initiatives alongside the courage, self-confidence, and diligence of entrepreneurs, Rajasthan has emerged as the fourth-largest state in the country in terms of MSMEs, boasting over 33 lakh such enterprises.

Over 1,600 Industrial Plots Allotted

The Chief Minister stated that the 'Direct Allotment Policy-2025' was implemented to ensure land availability for industries in the state, resulting in the allotment of over 1,600 industrial plots across the state within a year. Additionally, necessary reforms have been introduced across 23 priority sectors.

Furthermore, the timeframe for land-use approval for MSME units in urban areas has been reduced from 60 days to 30 days, and the deadline for issuing approvals required to commence industrial operations has been cut from 120 days to 30 days. Similarly, the 'White Category' list of non-polluting industries has been expanded from 104 to 877 industries, providing relief to thousands of MSMEs.

He stated that, keeping the future economy in mind, the government is developing new industrial hubs in the state, such as solar panel manufacturing parks, ceramic parks, data centre parks, and defence manufacturing parks. He mentioned that the government is formulating a development roadmap through the

'Viksit Gram-Ward Abhiyan' (Developed Village-Ward Campaign), an initiative aimed at securing global recognition for local products from every district. He further encouraged the youth to move towards becoming job creators by establishing processing units based on local agricultural products.

Industries & Commerce Minister Col. Rajyavardhan Rathore stated that the government is formulating policies and schemes to create an industry-friendly environment. He mentioned that the government has developed 33 new industrial areas, for which both financial and administrative approvals have been granted.

MoS for Industries & Commerce Shri K.K. Bishnoi said that under the leadership of Chief Minister Shri Bhajanlal Sharma, the state government is imparting new momentum to the MSME, skill development, and industrial sectors through innovation, good governance, and effective management.

During the event, the Chief Minister unveiled the Rajasthan Industrial Development Policy and the ODOP coffee table book, and launched the RAMP (Raising and Accelerating MSME Performance) portal. He distributed cheques worth over ₹13 crore-comprising loans, grants, and subsidies-to beneficiaries of various schemes under the Department of Industries and Commerce, and handed over land allotment letters and offer letters to beneficiaries of RIICO schemes.

Key announcements made by the Chief Minister:

- Development and operation of 'Haats' (markets) based on the PPP model for products made by artisans, weavers, and micro-enterprises; in the first phase, these Haats will be developed in Pushkar, Nathdwara, Jaisalmer, and Alwar.
- Financial assistance under the 'One District, One Product' scheme for processing units dealing with species and flora identified under the 'Panch Gaurav Yojana'.
- Reduction of the capital subsidy tenure for MSMEs under RIPS from 10 years to 7 years.
- Reduction of the minimum investment threshold to ₹15 crore under RIPS-2024 for selected component categories within the manufacturing package for the electronics and semiconductor sectors.
- While investment is currently permitted in a maximum of three phases under RIPS-2024, projects falling under the Government of India's ECMS scheme will now be allowed investment across five phases.
- Increase in the maximum monthly allowance for women and differently-abled personnel undergoing skill development and training in the electronics and semiconductor sectors-from ₹4,000 to ₹6,000.
- Financial assistance will be provided to 25 new startups this year through the Rajasthan Venture Capital Fund.

On this occasion, a large number of entrepreneurs attended the event, including Jaipur MP Smt. Manju Sharma, Chief Secretary Shri V. Srinivas, ACS (Industries and Commerce) Shri Shikhar Agarwal, and Commissioner Shri Nilabh Saxena.

Key Points of Yamuna Water Project MoA Finalized

Chief Minister Shri Bhajanlal Sharma participated in a meeting regarding the Yamuna Water Project in New Delhi, alongside **Union Minister for Jal Shakti Shri C.R. Patil** and **Haryana Chief Minister Shri Nayab Singh Saini** on 23rd June. During the meeting, various aspects related to the project's implementation were discussed in detail, and the key points of the Memorandum of Agreement (MoA) were finalized. Additionally, matters concerning the Kishau Dam project were deliberated upon.

Union Minister for Jal Shakti Shri C.R. Patil stated that under the guidance of Prime Minister Narendra Modi- and driven by the spirit that "if there is water, there is a future"- significant steps are being taken towards better water resource management through inter-state coordination. In this context, the Yamuna Water Project is being advanced with an effective and long-term perspective. He noted that the project proposes transporting water via pipelines rather than traditional canal systems; this approach will ensure water conservation while making the distribution network more extensive.

He further mentioned that issues concerning the six states involved in the Kishau Dam project have been resolved, and the relevant MoA will be signed soon. This will benefit Rajasthan, Delhi, Haryana, and other states.

Chief Minister Shri Bhajanlal Sharma stated that the Yamuna Water Project is of immense importance to Rajasthan, particularly the Shekhawati region. This project will prove pivotal for the region's socio-economic development and for improving the standard of living for lakhs of people. He affirmed that the state government is committed to implementing the project on the ground as soon as possible, with the cooperation of the Central and Haryana governments.

CM Inaugurates E-Mitra Sewa Portal at National e-Governance Conference held at Jaipur

Chief Minister Bhajanlal Sharma addressed the 29th National e-Governance Conference at Jaipur. He noted that in 2014, Prime Minister Narendra Modi initiated the effective use of technology. Consequently, the interference of middlemen was eliminated through the 'Jan-Dhan, Aadhaar, and Mobile' (JAM) trinity. Direct Benefit Transfer (DBT) ensured that benefits from every scheme reached the beneficiaries' accounts directly, while Digital India and UPI gained significant momentum. The Chief Minister launched the SMART project, the e-Mitra WhatsApp service, and the Rajasthan Innovation Challenge; he also unveiled a coffee-table book. Earlier, he inaugurated and visited an exhibition showcasing technology-based services.

On this occasion, Information Technology and Communication Minister Col. Rajyavardhan Rathore, Parliamentary Affairs Minister Shri Jogaram Patel, Chief Secretary Shri V. Srinivas, Secretary of Electronics and Information Technology Shri S. Krishnan, Secretary of Administrative Reforms and Public Grievances Smt. Nivedita Shukla Verma, and Secretary of the Department of Information Technology and Communication Shri Ravi Kumar Surpur were present. Subsequently, the Chief Minister participated in a round-table discussion with industry representatives.

❑ ❑ ❑

LUB's News in Brief

An important MoU was signed to organize 'India Stone-Mart 2028' by the Rajasthan State Industrial Development and Investment Corporation (RIICO), Centre for Development of Stones (CDOS), and Laghu Udyog Bharati at Jaipur on 17th June.

On this occasion, LUB's National Organizing Secretary Shri Prakash Chandra Ji, Former National President Shri Ghanshyam Ojha, and National Jt. GS Shri Naresh Pareek; RK Marble Group Chairman Shri Ashok Patni; Minister of Industries & Commerce Col. Rajyavardhan Singh Rathore; MoS-Industries & Commerce Shri K.K. Bishnoi; ACS Shri Shikhar Agrawal; RIICO MD Shri Suresh Ola; India Stonemart Convener Shri Natwar Ajmera; CDOS Vice Chairman Shri Deepak Ajmera; FIGSI General Secretary Shri Manoj Singh, Vice Chairman Shri Sundar Somani; and STONA Chairman Shri Himanshu Sehgal were present.

Under the able leadership of Rajasthan Chief Minister Shri Bhajanlal Sharma, the state government aims to develop state into an industrial hub, thereby creating maximum employment opportunities for the youth. Special emphasis was placed on initiating preparations well in advance to ensure a grand scale for the 2028 event, establishing dialogue with entrepreneurs from the domestic and international stone industries, and familiarizing national and international architects with the unique qualities of Rajasthan's stone.

A detailed discussion took place also between government officials and industry representatives regarding new technologies, innovation, global market prospects, export promotion, and challenges within the stone industry.

National Org. Secretary Shri Prakash Chandra Ji interacted with Phagwara Unit members on 12th June. During the meeting, various issues and challenges being faced by the industrial community were discussed in detail. He assured them that all valuable inputs would be placed before the competent authorities for appropriate consideration and necessary action. On this occasion, National VP Shri Arvind Dhumal, State President Shri Pardeep Mongia, Secretary Shri Vivek Rathour, Media In-charge Shri Anuj Kapoor, NE Member Shri Amit Goel, Unit President Shri Inder Paul Khurana, Vice President Shri Puneet Gupta, Secretary Shri Arvind Bagga, Former President Shri Pankaj Gautam were present.

LUB's Kathua unit of J&K (UT) organized a one-day interactive session on MSMEs and organizational structure across the Union Territory on 13th June. National Org. Secretary Shri Prakash Chandra ji spoke about the glorious history of Bharat and

explained that during the tenure of former Prime Minister Shri Atal Bihari Vajpayee Ji, a decision was taken to give special attention to small industries, which later led to the strengthening of the MSME Ministry. He added that quality, productivity and cost control are essential for industries to remain competitive in the present business environment.

NWC Member Shri Parveen Pargal demanded extension of the NCSS package and immediate release of benefits to 602 industrial units which have already applied online and offline and made investments. He also demanded a fresh 10-year Central Package for micro, small and existing industries in J&K.

A new team for Kathua unit was announced-Shri Manoj Goyal as President, Shri Rajinder Gupta Senior Vice President, Shri Rahul Jain Vice President, Shri Piyush Rastogi General Secretary, Shri Mohit Bhatia and Shri Arun Sharma as Secretaries, and Shri Nitish Kumar as Treasurer.

Shri Arvind Dhumal- National VP and Prabhari North Zone; Shri Vivek Rathore-State GS Punjab; Shri Vikrant Sharma-North Zone Head, Mass Comm., Shri Dinesh Gupta-President J&K; Shri Aagam Jain-State GS and Shri Ishant Gupta-State Treasurer were present.

A benefit distribution program under the Pradhan Mantri Viksit Bharat Rojgar Yojana (PM-VBRY) was organized by the Ministry of Labour and Employment, Govt. of India, at the CAZRI campus in Jodhpur on 19th June. This event was virtually linked to the national-level program held at Vigyan Bhawan, New Delhi, where Prime Minister Shri Narendra Modi distributed incentive amounts totaling approximately ₹2,400 crore to over 1.5 million beneficiaries across the country. Rajya Sabha MP Shri Rajendra Gehlot, Jodhpur City MLA Shri Atul Bhansali, and former National President of Laghu Udyog Bharati Shri Ghanshyam Ojha participated in this divisional-level event. Shri Ojha provided detailed information regarding the activities of Laghu Udyog Bharati, the development of the MSME sector, and the crucial role industries play in job creation.

LUB's Bihar state delegation led by State President Shri Shyamsundar Bhimseria, met with Chief Minister Shri Samrat Chaudhary and presented a memorandum of key issues and demands concerning the state's industries and the MSME sector.

A joint executive meeting for Udaipur was held in the presence of National Org. General Secretary Shri Prakash Chandra Ji and State President Shri Yogendra Sharma on 17th June. Udaipur City President Shri Rajendra Surana informed the gathering that RIICO has allotted 2,000 sq. meters of land in the Kaladwas Extension area to the organization for the construction of a building and a skill development center. Documents related to the land allotment were presented to both officials. City unit Secretary Shri Shubham Dangi proposed the vote of thanks.

LUB's Moradabad Team (Uttar Pradesh) discussed the problems of MSME sector and its exports with Dy. Chief Minister Shri Keshav Prasad Maurya. The team presented a memorandum also on 14th June.

Laghu Udyog Bharati Uttarakhand delegation led by State President Dr. Vijay Singh Tomar meets Medical & Health Minister Shri Subodh Uniyal on important issues related to the pharmaceutical industry, medical systems, health services, and the state's industrial sectors on 27th June. On this occasion, the delegation included State VP Shri Gyan Prakash Painuli & Shri Deepak Goyal, State Jt. GS Shri Mayank Garg, District GS (Dehradun Metropolitan) Shri Rakesh Malhotra, and District Coordinator Shri Divyanshu Painuli.

Shri Ashok Dinda, MoS MSME, West Bengal, highlighted the importance of MSME sector on International MSME Day Celebration program organised by Laghu Udyog Bharati on 27th June. He expressed confidence that in coming days efforts of Laghu Udyog Bharati to strengthen MSME sector will lay a strong foundation for Viksit Bharat and Viksit West Bengal. He also assured for utmost support of West Bengal Govt. for fast resolutions of cases for reopening of closed MSME units, setting up of new MSME units and smooth running and scaling up of existing MSME units with an effective Single Window system. He assured of MSME friendly industrial policy, fast development of roads and other infrastructure and ample availability of land for growth of MSME sector.

Shri Arup Kumar Roy, General Secretary of Central Sambhag, West Bengal met Sushri Agnimitra Paul Cabinet Minister-Urban Development and Municipal Affairs and discussed various aspects of development of Industrial Estate's civic conditions 27th June.

LUB's delegation led by National Vice President Shri Arvind Dhumal met with BJP National President Shri Nitin Nabin and submitted a memorandum regarding issues related to cottage, micro, small, and medium enterprises on 24th June.

On this occasion, National GS Shri Tarun Chugh, Punjab BJP President Shri Kavel Singh Dhillon, State

Co-Incharge Dr. Narinder Singh Raina, Coordinator Mass Comm. North Zone Shri Vikrant Sharma, State GS Shri Vivek Rathi, Ludhiana District President Shri Tarun Jain & General Secretary Shri Gaurav Arora, Secretary Shri Amit Dogra, Jalandhar District President Shri Anirudh Dhir, BJP Jalandhar District President Sushil Sharma, and other members were present.

LUB's Ludhiana unit organized an Awareness Program on the MSME Competitive Lean Scheme on 11th June. National Org. Secretary Shri Prakash Chandra ji stated that quality, productivity, and cost control are crucial for industries in the current era of competition. He remarked that by adopting the lean manufacturing system, industries can enhance their competitiveness by reducing production costs, improving quality, and eliminating unnecessary waste. Entrepreneurs were present, including National VP Shri Arvind Dhumal, Punjab State President Shri Pradeep Mongia, and District President Shri Tarun Jain.

LUB Maharashtra State unit organized a program on "The Role of MSMEs in Maharashtra's Goal of

Becoming a One-Trillion-Dollar Economy on 20th June. On this occasion, Chief Advisor to CM Shri Kaustubh Dhavse emphasized that small industries form the backbone of Maharashtra's economy, and large-scale projects cannot succeed without their support. He spoke about sectoral opportunities, regional industrial growth and Japanese cluster. He stressed the need to reduce interest rates on MSME loans to encourage growth. He said that entrepreneurs must embrace Artificial Intelligence to remain competitive in rapidly changing markets. State President Shri Amit Ghaisas told that LUB members strongly demanded for the creation of a dedicated MSME ministry within the state government.

❑ ❑ ❑

During a visit to Batala, an important meeting with local entrepreneurs was held under the guidance of National Org. Secretary Shri Prakash Chandra Ji and National VP Shri Arvind Dhumal. Detailed discussions took place regarding strengthening railway connectivity, addressing GST-related issues, and tackling other common challenges faced by the industrial sector.

LUB's Tamil Nadu delegation invites Union MoS for MSMEs Ms. Shobha Karandlaje for Mega MSME Exhibition and Buyer-Seller Meet to be held at Hosur on Sept. 18-19. Former National President Shri HVS Krishna, National Jt. GS Shri M. Mohana Sundaram, State President Shri Verchezien, State Jt. GS Shri Jayendran, Hosur Unit President Shri Sivakumar, and Unit Secretary Shri Karuppaiyah were present.

LUB's Kerala state unit hosted EC meeting on the pravas of National Org. Secretary Shri Prakash Chandra ji for strategic planning on MSME sector. On this occasion, Shri Suresh kumar T.O.-State President, Shri Venkatesh S.-Vice President, Shri Vijaya-raghavan- National VP, Shri Sivakumar AIWC member, Shri Vinod N.K.-Organising Secretary, Shri Narayanan Pillai-NWC Member, Shri Venkatesh S.-Vice President and Shri Prasanth S. Menon- Jt. GS were present.

....

A delegation from Laghu Udyog Bharati expressed gratitude to Shri Gulab Chand Kataria, Governor-

Punjab & Administrator of UT Chandigarh for his efforts towards industrial development and the welfare of entrepreneurs. During the meeting, State President Shri Pradeep Mongia requested the allotment of land for a skill development center aimed at providing employment-oriented training to the youth. President Chandigarh Shri Avi Bhasin and GS Shri Manish Nigam were also present.

During pravas (visit) at Chandigarh, National Org. Secretary Shri Prakash Chandra ji provided guidance on the expansion of the organization, its activities, and various organizational matters in a meeting with EC members. National VP Shri Arvind Dhumal, West-Northen Co-Incharge Shri Shubh Aadesh Mittal, Unit President Shri Avi Bhasin, General Secretary Shri Manish Nigam and other members were present.

During the pravas in Himachal Pradesh, National

Org. Secretary Shri Prakash Chandra ji formally announced the new executive committee of Paonta Sahib unit. He called upon the newly appointed team to play an active role in further strengthening the organization and resolving issues faced by the industrial sector. On this occasion, National VP Shri Arvind Dhumal, along with West-Northern Co-Incharge Shri Shubh Aadesh Mittal, NWC Member Shri Vikram Bindal, State President Shri Akhil Mohan Agarwal and General Secretary Shri Ashwani Kumar were notably present.

LUB's Bathinda Unit (Punjab) organised an interactive session on the pravas of Shri Prakash Chandra Ji-National Org. Secretary on 8th June. Shri Arvind Dhumal-National VP, Shri Pardeep Mongia-State President, Shri Anil Sharma-State Jt. GS, Shri Vikrant Sharma-Communication Prabhari, Shri Sarup Chand Singla President-BJP Bathinda and Shri Ramnik Walia- Zila Sangh Sangchalak shared their valuable suggestions for MSME sector.

An informative seminar was organized by LUB's Kala Amb Unit (HP) in which National Org. Secretary Shri Prakash Chandra ji provided guidance. On this occasion, National VP Shri Arvind Dhumal, West-Northen Co-Incharge Shri Shubh Aadesh Mittal, National Executive Member Shri Vikram Bindal, State President Shri Akhil Mohan Agarwal and General Secretary Shri Ashwani Garg, Unit President Shri Akhil Maheshwari, General Secretary Shri Dhyan Singh, and Treasurer Shri KC Pareek participated in the group discussion.

Chief Minister Shri Nayab Singh Saini launched 'Make in Haryana Industrial Policy-2026' in the presence of Industry & Commerce Minister Shri Rao Narbir Singh at Gurugram on 1st June. On this occasion, LUB's Haryana Team- NWC Member & Haryana In-charge Shri Arun Bajaj, State GS CA Manoj Rungta, Shri Vinod Gupta, Shri Vinod Wadhwa and Shri Pawan Gupta felicitated the Chief Minister.

LUB's Haryana state unit conducted a Regional Conference in the presence of National President Shri Madhusudan Dadu and West-Northen region Co-Incharge Shri Shubh Adesh Mittal at Yamuna Nagar on 8th June. The conference was organized with the aim of creating a positive environment for organizational unity, coordination among entrepreneurs and future action planning. On this occasion, newly appointed state President Shri Raman Saluja was also felicitated.

Former Union Minister- Jal Shakti Shri Gajendra Singh Shekhawat and former Chief Minister of Uttarakhand & MP-Haridwar constituency Shri Trivendra Singh Rawat attended the Prabuddh Varg Sammelan organized by the Dehradun Mahanagar unit on 12th June. They held a special interaction with representatives of Laghu Udyog Bharati and commended the organization's activities. State President Dr. Vijay Singh Tomar was also felicitated.

On this occasion, LUB's state In-charge Shri Kailash Mailana; State VP Shri Rajiv Goyal, Shri Pradeep Khanduri, and Shri Gyan Prakash Painyuli; State Membership In-charge Shri Rahul Dev Dand; Jt. State GS Shri Mayank Garg; EC member Shri Rajesh Jaiswal; and unit President Shri Kamaljit Sharma were also present.

A cordial meeting of Laghu Udyog Bharati was held with Dr. Rajneesh-IAS, Additional Secretary & Development Commissioner (MSME), GoI, led by Shri Om Prakash Gupta National General Secretary, Shri Naresh Pareek National Jt. GS, Smt. Anju Bajaj National Secretary, and Shri Diwan Chand Gupta-President, Delhi Prant at Kartavya Bhawan, New Delhi on 8th June. The meeting focused on the upcoming India Industrial Fairs to be held in Raipur, Chhattisgarh and Gujarat. Discussions also covered key issues concerning MSMEs and future developmental initiatives.

'Udyami Samwad' Program was organized under the joint aegis of LUB Agra, and the State Tax Department (SGST) on 10th June.

During the event, a detailed representation regarding major GST-related issues was submitted to the department. District President Shri Vijay Gupta stated that instead of the department demanding years-old toll reports, the system should be automatically linked to the E-Way Bill Portal; this would enhance both transparency and compliance.

Shri Pankaj Gandhi, Additional Commissioner (Grade-1) of the State Tax Department, Agra, assured that any local-level issues capable of being resolved at the departmental level would be addressed swiftly and positively.

Shri Rakesh Garg, Chairman-Uttar Pradesh Small Industries Corporation, highlighted the state government's industry- and trade-friendly policies. A large number of entrepreneurs, traders, and departmental officials attended the event, including CA Nikhil Gupta, State Secretary Shri Manish Agarwal, Treasurer Shri Sanjeev Jain, CA Nitesh Gupta, CA Alok Agarwal, Shri Ankur Agarwal, Shri Arvind Shukla, Vice President Shri Dinesh Gupta, Shri Shailesh Agarwal, and Shri Anuj Singhal. District General Secretary Shri Rajiv Bansal proposed the vote of thanks.

To mark the centenary year of the RSS, a blood donation camp was organized by Laghu Udyog Bharati at Sudisha Foundry in Seraikela-Kharsawan, Jharkhand. Attendees included Shri Dinesh Ranjan-Assistant Regional Director, JIADA, Shri Indra Agrawal, National Secretary In-charge, Jharkhand & Bihar), Shri Sanwarmal Sharma (Provincial Secretary), Shri Vinod Sharma (District President), Shri Sapan Majumdar-General Secretary, and Shri Manoj Sahay-Vice President. A total of 216 units of blood were collected.

LUB North Bengal heartily welcomes launch of PM Vikshit Bharat Rojgar Yojna. The Darjeeling region also celebrated in the presence of Shri Raju Bista- MP Darjeeling and LUB's senior Shri Praveen Agarwal.

LUB's Bareilly unit (UP) organized a FOSTAC seminar on 6th June. Training was provided to all participants and FSSAI certificates were distributed. Shri Rahul Singh and CFSO Shri Akshay Goyal shared their views on enhancing food safety and raising awareness.

Several pending cases were resolved during a meeting held on June 4, attended by Madhya Pradesh MSME Minister Shri Chaitanya Kashyap, LUB's State General Secretary Shri Arun Soni, and other office-bearers.

LUB's Goa state President Smt. Pallavi Salgaocar was honoured with Nari Shakti Samman-2026 in the special program organised in the fond memory of Rajmata Ahilya Devi Holkar by Department of Rural Development, Govt. of Goa and Sammruddhi Foundation.

LUB' J&K unit organized an interactive program at Anantnag focused on MSME activities. The event facilitated dialogue with women entrepreneurs, and artisans, and included the distribution of handicraft cards issued by Ministry of Textiles, Govt. of India. National VP Shri Arvind Dhumal, Shri Samir Mundra and J&K In-charge Shri Parveen Pargal were present on the occasion.

❑ ❑ ❑

सत्यमेव जयते
राजस्थान सरकार

श्री नरेन्द्र मोदी
माननीय प्रधानमंत्री

श्री भजनलाल शर्मा
माननीय मुख्यमंत्री

अभियान के प्रमुख उद्देश्य

- जल संरचनाओं का जीर्णोद्धार
- जल स्रोतों को प्रदूषण से मुक्त करना
- पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता
- भूजल पुनर्भरण हेतु जागरूकता
- व्यवहार परिवर्तन से बेहतर जल उपयोग
- हरियालो राजस्थान की तैयारी
- जल संरक्षण जन-जन का अभियान
- जल संरचनाओं की स्वच्छता हेतु जागरूकता
- जल बचत हेतु जन जागृति
- कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान से हर बूंद का संचयन
- जल संचय जन भागीदारी बढ़ाना

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान

UDYOG TIMES
OFFICIAL PUBLICATION OF LAGHU UDYOG BHARATI
30 June - 2026
Registration No. RAJBIL/2016/69093
Postal Reg. No. : Jaipur City/433/2020-22

15th INDIA INDUSTRIAL FAIR UDYAM 2026

लघु उद्योग भारती
LAGHU UDYOG BHARATI (GUJARAT)

SH. NARENDRA MODI
HON'BLE PRIME MINISTER

SH. BHUPENDRA PATEL
HON'BLE CHIEF MINISTER

PROSPEROUS GUJARAT FOR A VIKSIT BHARAT UNDER VISIONARY & DYNAMIC LEADERSHIP

15TH INDIA INDUSTRIAL FAIR 2026

THE LARGEST EXPO IN GUJARAT REGION

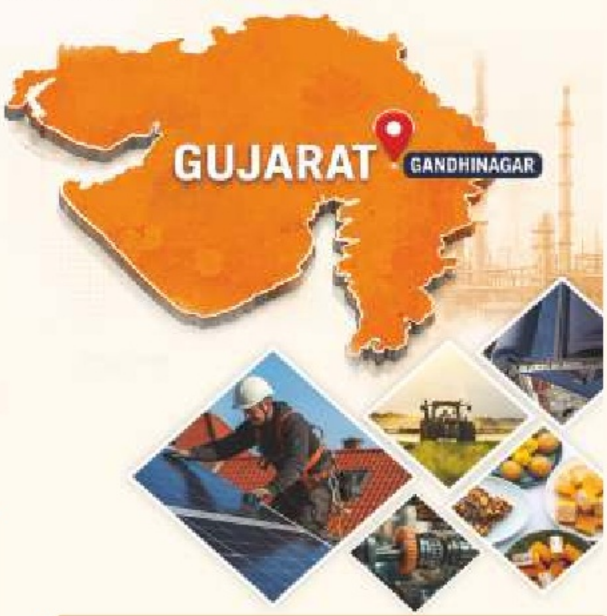

VENUE:
HELIPAD GROUND, GANDHINAGAR, GUJARAT

DATES:
23TH TO 26TH OCTOBER 2026

WHY EXHIBIT?

- Excellent Networking & B2B Matchmaking Opportunities
- Direct Business & Investment Opportunities
- Technical Seminars, Workshops & Industry Conferences
- Product Launches & Live Technology Demonstrations
- Vendor Registration Support for Government Departments & PSUs
- Platform to Connect with Manufacturers, Dealers, Distributors & Buyers
- Opportunities for MSMEs, Start-ups and Industrial Suppliers to Expand Market Reach

Limited Stalls Book Early!

INVITING EXHIBITORS FOR STALL BOOKING

Be a part of one of India's leading industrial exhibitions and showcase your business to a national audience.

EVENT HIGHLIGHTS

- 400+ Exhibition Stalls
- 50,000+ Sq. Mtr. Exhibition Area
- 1,50,000+ Expected Visitors
- ₹1000 CRORES Business (Approx.)

For More Details

VAJUBHAI VAGHASIYA +91 98243 00526
RAMESHBHAI THUMMAR +91 98254 62308
DEVANGBHAI PATHAK +91 98252 45610
STALL BOOKING +91 88667 56788

EMPOWERING MSMES | DRIVING INNOVATION | CREATING OPPORTUNITIES

Follow us
lubindia
lubindia
@lubBharat
lub.india
laghu-udyog-bharati

LUB's Monthly Magazine Published by Madhu Sudan Dadu Printed at Raj Blocks, 22 Godown Ind. Area Kartapura, JAIPUR-302019